सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 232, नई दिल्ली | शुक्रवार, 03 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

ऊँचाई पर वही पहुँचते है, जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते है।

# दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, इन कामों पर लगी पाबंदी

## हल्के कमर्शियल समेत इन वाहनों की राजधानी में एंट्री बैन

संजय बाटला

दिल्ली–एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को दिल्ली के इलाकों में 450 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली–एनसीआर में गैर–जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए।

**नई दिल्ली।** दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को कई इलाकों में 450 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए।

**ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू**

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद की है। समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गईं।

**इन वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन**

ग्रेप-3 के अंतर्गत आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूरी तरह से पांबदी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल वाले ट्रकों और मध्यम और भारी माल वाहनों (आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर) के एंट्री पर बैन रहेगा।

### कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा प्रदुषण नियंत्रण के प्रति नया दिशा निर्देश जारी

वायु प्रदुषण को बढ़ते देख उनके नियंत्रण के लिए जारी हुए नए दिशा निर्देश पर जारी सभी बंदिशे फिर से वाहनों फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन पर। पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली और चल रही इंडस्ट्री से आने वाले वायु प्रदुषण की रोक के लिए नही जारी किए कोई दिशा निर्देश, आखिर क्यों ? क्या सच में सिर्फ कुछ वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने से प्रदुषण नियंत्रण में आ जाता हैं, बड़ा सवाल ?

**आपकी जानकारी हेतु दिशा निर्देश की कापी**

(i) Enforce strict ban on construction and demolition activities in the entire NCR, except for the following categories of projects:
a. Projects for Railway services / Railway stations
b. Projects for Metro Rail Services and stations
c. Airports and Inter State Bus Terminals
d. National security/ defence related activities/ projects of national importance;
e. Hospitals/ health care facilities
f. Linear public projects such as highways, roads, flyovers, over bridges, power transmission/distribution, pipelines etc.
g. Sanitation projects like sewage treatment plants and water supply projects etc.;
h. Ancillary activities, specific to and supplementing the above noted categories of projects.

**Note:** The above exemptions shall be further subject to strict compliance of the C&D Waste Management Rules, dust prevention/ control norms including compliance with the directions of the Commission issued from time to time in this regard.

(ii) Other than the projects exempted under (i) above, dust generating/ air pollution causing C&D activities to be strictly banned during this period shall include:
- Earthwork for excavation and filling including boring & drilling works.
- All structural construction works including fabrication and welding operations.
- Demolition works.
- Loading & unloading of construction materials anywhere within or outside the project sites.
- Transfer of raw materials either manually or through conveyor belts, including fly ash.
- Movement of vehicles on unpaved roads.
- Operation of batching plant.
- Laying of sewer line, waterline, drainage work and electric cabling by open trench system.
- Cutting and fixing of tiles, stones and other flooring materials.
- Grinding activities.
- Piling work.
- Water proofing work.
- Painting, Polishing and varnishing works etc.
- Road construction/ repair works including paving of sidewalks / pathways and central verges etc.

17 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस. टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23701213, ई -मेल : caqm-ncr@gov.in
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg, New Delhi-110001
Tel:011-23701213, E-mail: caqm-ncr@gov.in

(iii) For all construction projects in NCR, non-polluting / non-dust generating activities such as plumbing works, electrical works, carpentry related works and interior furnishing / finishing / decoration works (excluding painting, polishing and varnishing works etc) shall be permitted to be continued.

5. Close down operations of stone crushers
6. Close down all mining and associated activities in the NCR.
7. NCR State Govts. / GNCTD to impose strict restrictions on plying of BS III petrol and BS IV diesel LMVs (4 wheelers) in Delhi and in the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar.
8. State Govts. in NCR and GNCTD may take a decision on discontinuing physical classes in schools for children up to Class V and conducting classes in an online mode.

Further, citizens may be urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the region, as under:
- Walk or use cycles for small distances.
- Choose a cleaner commute. Share a ride to work or use public transport.
- People, whose positions allow working from home, may work from home.
- Do not use coal and wood for heating purpose.
- Individual house owners may provide electric heaters (during winters) to security staff to avoid open burning.
- Combine errands and reduce trips.

(R.K. Agrawal)
Director (Technical)
(Member & Convenor of Sub-Committee on GRAP)

17 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस. टी.सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23701213, ई -मेल : caqm-ncr@gov.in
17th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan (STC Building), Tolstoy Marg, New Delhi-110001
Tel:011-23701213, E-mail: caqm-ncr@gov.in

**GOVT OF NCT OF DELHI: TRANSPORT DEPARTMENT**
**5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110054**

F.No.23(1697)/CAP/TPT/PCD/2022/Pt. File
CD No. 075714609
Dated : 02.11.2023

**ORDER**

**Subject :-** **Implementation of Action under Stage – III ('Severe' air quality of revised GRAP in Delhi NCR steps to be taken**

The Sub-Committee for operationalisation of the revised GRAP has reviewed the air quality scenario as well as the forecasts for meteorological conditions and Air Quality Index in Delhi. The Sub-Committee vide order No.120017/27/GRAP/2021/CAQM dated 02.11.2023 has invoked all the actions as envisaged under **Stage – III** of the GRAP – 'Severe' Air Quality (Delhi AQI ranging between 401 -450), with immediate effect in the NCR, with immediate effect, in addition to all the actions under Stage – I and Stage – II of the GRAP.

As per directions as provided under Stage – III of the revised GRAP and under Section 115 of Motor Vehicle Act, 1988, it is hereby ordered that there shall be restrictions to ply BS-III, petrol and BS-IV, diesel LMVs (4 Wheelers) in NCT of Delhi, with immediate effect till further orders (*Except for vehicles deployed in Emergency Services, Police vehicles & Govt. vehicles used for Enforcement*).

If any BS-III, Petrol and BS-IV, Diesel LMV (4 Wheeler) found plying on roads will be prosecuted under Section 194(1) of Motor Vehicle Act, 1988, which provides a fine of Rs.20,000 -.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yogesh Jain
Dy. Commssioner (Transport)

*To :-*

1. Spl. Commissioner, Delhi Traffic Police, Dev Prakash Shastri Marg, Delhi – 110012
2. Nodal Officer (Traffic), Delhi Police
3. Dy. Commissioner (Enforcement), Transport Deptt., GNCTD
4. Sr. System Analyst, Transport Deptt., - *for uploading this order on the website of Transport Department.*

*Copy for Information to :-*

1. Secretary, Hon'ble Minister of Transport, GNCTD
2. PS to Pr. Secretary cum Commissioner, Transport Department, GNCTD
3. Director (Environment), Deptt. of Environment, Govt. of NCT of Delhi

Yogesh Jain
Dy. Commssioner (Transport)

# दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा 3 नवम्बर 2023 को BS 3/4 डीजल बसों को दिल्ली में बंद करने के खिलाफ घोषित धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और सीएक्यूएम प्रदूषण की आड़ में ट्रांसपोर्टर्स को बर्बाद करने पर लगे हैं. यहां यूनियन अध्यक्ष का कहना है वास्तव में इन सभी को पता हैं की

प्रदूषण पराली जलने से उठने वाले धुएं या कंस्ट्रक्शन के समय उठने वाली धुल मिट्टी और सर्दी के मोसम में वायु के बदलाव के कारण होता है. लेकिन इन्हें इल्जाम लगाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट लगते हैं. उन्होने यह भी कहा की यह सब मिलकर BS 6 डीजल पेट्रोल की कारो और बसों के साथ इलेक्ट्रिक कारे - बसें बनाने वाली कम्पनियो को फायदा दिलाना चाहते हैं ? उन्होने साथ में बताया इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वाल्टी मैनेजमेंट, दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को दिल्ली में रात के वक़्त आने जाने वाले लाखों की संख्या में डीजल ट्रक दिखाई नहीं देते जो प्रदूषण करके निकल जाते हैं.

संजय सम्राट का कहना हैं की हमने इस से पहले भी कई बार इस मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा हैं लेकिन सरकार, सीएक्यूएम और ट्रांसपोर्ट विभाग ने हमारी मांगो को ना सुना और ना ही मिलने का समय दिया.

हमारी मांगे हैं की हमारी व्यवसायिक नम्बर की टैक्सी बसों को उसके लिए निर्धारित आयु सीमा तक बिना किसी रुकावट/ बंदिश के चलने दिया जाए. और ग्रेप सिस्टम से व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकृत टैक्सी / बसों को बाहर रखा जाए क्योंकि यह वाहन जनता को सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किए जाते हैं और इन्ही वाहनों से वाहन मालिको और चालको के घरों का दाल रोटी चलती हैं। उन्होने अन्त में कहा की अगर आपको हमारे वाहनों को रोकना हैं तो हमे प्रति दिन के हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाए।

नेशनल हाइवे 44

# रामबन पुल बनकर तैयार... जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर सुगम यातायात में एक और बाधा पार

परिवहन विशेष न्यूज

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यातायात और भी सरल होने जा रहा है। रामबन में 1.08 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बन कर तैयार हो गया है। फोरलेन यातायात के लिए इस पुल को जल्द ही खोल दिया जाएगा।

**जम्मू।** जम्मू-श्रीनगर (राष्ट्रीय राजमार्ग-44) पर सुगम यातायात की दिशा में एक और बाधा दूर कर ली गई है। 328 करोड़ रुपये की लागत से 1.08 किलोमीटर लंबा पर रामबन पुल को तैयार कर लिया गया है। फोरलेन यातायात के लिए पुल को शीघ्र खोल दिया जाएगा। यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दी। उन्होंने पुल की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। फोरलेन पुल पर यातायात शुरू होने से रामबन के स्थानीय बाजार में लगने वाले जाम से निजात मिलने के साथ कश्मीर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अमरनाथ यात्रा के दौरान टू लेन यातायात शुरू कर दिया गया था।

पोस्ट पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि रामबन में यह असाधारण पुल 26 स्पैन से बना है और इसके संरचनात्मक डिजाइन में कंक्रीट और स्टील गर्डर्स के संयोजन का उपयोग किया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की गति बढ़ाने के साथ उनकी समय की बचत करेगा।

**पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से मिला उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा**

नितिन गडकरी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को उत्कृष्ट राजमार्ग बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा रहा है। यह स्मारकीय उपलब्धि न केवल क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है, बल्कि एक शीर्ष स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में इसके आकर्षण को भी बढ़ाती है।

# मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी: अब डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे अपना सामान, मोमेंटम 2.0 एप से कर पाएंगे ई-शॉपिंग

परिवहन विशेष न्यूज

डिजिटल लॉकर की सुविधा अभी केवल 50 स्टेशनों पर उपलब्ध है। यह वर्ष 2024 के जून के अंत तक अधिकांश स्थानों पर प्रदान किए जाएंगे। वहीं, दिल्ली मेट्रो इस सहूलियत से एनसीआर में यात्रियों के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक परिवहन सेवा बन गई है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के 'मोमेंटम 2.0 एप' के माध्यम से क्यूआर टिकटिंग (मेनलाइन और एयरपोर्ट लाइन), ई-शॉपिंग, तत्काल डिलीवरी के लिए डिजिटल लॉकर, स्मार्ट यूटिलिटी भुगतान और लास्ट माइल कनेक्टिविटी विकल्प की सुविधा ले सकते हैं। वर्चुअल स्टोर्स वर्तमान में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, बाराखंभा रोड मेट्रो स्टेशन, द्वारका मोड़ व शिवाजी स्टेडियम समेत सात लाइनों के 20 स्टेशनों पर प्रदान किए गए हैं।

वहीं, डिजिटल लॉकर की सुविधा अभी केवल 50 स्टेशनों पर उपलब्ध है। यह वर्ष 2024 के जून के अंत तक अधिकांश स्थानों पर प्रदान किए जाएंगे। वहीं, दिल्ली मेट्रो इस सहूलियत से एनसीआर में यात्रियों के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक परिवहन सेवा बन गई है। इसका उद्देश्य सुगम यात्रा, यात्रियों के आवागमन समय को गुणवत्तापूर्ण, प्रोडक्टिव ब्लॉक्स में परिवर्तित करना है।

**कार्ड की बैलेंस राशि हुई खत्म तो ऑटो टॉप के जरिये मिलेगा प्रवेश**

इसमें खास बात यह है कि कार्ड का बैलेंस न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम हो जाता है तो यात्रियों के लिए एप में ऑटो टॉप अप के स्थायी निर्देश का विकल्प भी उपलब्ध है, जो कि सीधे बैंक खाते से जुड़ा है। वहीं, टिकट का भुगतान सीधे खाते से हो जाएगा। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर बुधवार को 'मोमेंटम 2.0' एप लॉन्च किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं के लिए एक एप बनाया है। यह एआई पर आधारित है, जो कि यात्रियों की पसंदीदा व जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। एक निजी कंपनी द्वारा संचालित यह नया एप यात्रा के समय को ध्यान में रखते हुए मेट्रो में सवार होने तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। वहीं, मेट्रो प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभी केवल आईओएस पर उपलब्ध है, आने वाले 48 घंटों में यह एंड्रॉइड पर उपलब्ध होगा।

**स्टेशन व एप में यह सुविधा होगी उपलब्ध**

**सुव्यवस्थित क्यूआर टिकटिंग**

'मोमेंटम 2.0' क्यूआर टिकटिंग मेट्रो में प्रवेश को सुगम बनाता है। यह एयरपोर्ट लाइन सहित सभी मेट्रो लाइनों के लिए एकीकृत क्यूआर टिकट सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए कई एप रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा डीएमआरसी कार्ड रिचार्ज के साथ-साथ कार्ड के लेनदेन विवरण भी एप पर उपलब्ध हैं। साथ ही यात्रियों को अपनी यात्रा और रिचार्ज हिस्ट्री के बारे में जानने में मदद मिलेगी।

**वर्चुअल स्टोर्स पर खरीदारी**

इस एप में सामान की एक विस्तृत श्रृंखला से सामान चुनने के साथ ही ई-शॉपिंग विकल्प है। यह अनोखा ब्रिक एंड क्लिक स्टोर ग्राहकों को मेट्रो स्टेशनों पर किराने का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की सुविधा प्रदान करेगा। ब्रांड अपने उत्पादों और सेवाओं को रियलिटी टूल्स का विस्तार कर प्रदर्शित कर सकते हैं और यात्री केवल क्यूआर कोड का उपयोग कर अपना पसंदीदा सामान खरीद सकते हैं।

**स्मार्ट शॉपर के लिए डिजिटल लॉकर**

घर पर न होने पर भी अपनी खरीदारी की वस्तुओं को सुरक्षित रूप से प्राप्त करने के इच्छुक यात्रियों के लिए डीएमआरसी के पास स्मार्ट बॉक्स विकल्प है। मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित ये नवीन डिजिटल लॉकर पार्सल और अन्य उत्पादों का सुरक्षित और तकनीक-सक्षम प्रबंधन करते हैं, जिससे डिलीवरी और पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सुनिश्चित होगी है। इसका उपयोग बैंक जैसे संस्थानों द्वारा चेक बुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को वितरित करने के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भी किया जा सकता है। वर्तमान में डिजिटल लॉकर्स 50 स्टेशनों पर प्रदान किए गए हैं और 2024 के जून के अंत तक अधिकांश स्थानों पर प्रदान किए जाएंगे।

**बिजली के बिल व फास्ट टैग की सुविधा**

उपरोक्त के अलावा और भी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिसमें उपयोगकर्ता अपने घरेलू बिल जैसे बिजली, गैस, मोबाइल, डीटीएच, फास्ट टैग आदि का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। एप में स्मार्ट कार्ड के लिए ऑटो टॉप अप की एक अतिरिक्त सुविधा भी मौजूद है।

**एप से मिलेगी स्टेशन की जानकारी**

यात्री मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर एप में स्टेशन की जानकारी के साथ-साथ कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जैसे गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म और पहली और अंतिम ट्रेन के समय की जानकारी भी मिलेगी। यही नहीं सटीक समय पर यात्रियों के लिए बाइक व कैब की जानकारी भी इसमें उपलब्ध होगी।

**फूड आउटलेट व एटीएम की भी मिलेगी सुविधा**

अगर किसी यात्री को फूड आउटलेट या एटीएम की तलाश होगी तो यह एप उसकी भी जानकारी देगा। एप से उनका पता लगाना आसान है। एप स्टेशनों पर उपलब्ध दुकानों, आउटलेट, कियोस्क और एटीएम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बस इन आउटलेट्स को ब्राउज करें और आगमन या प्रस्थान के दौरान अपनी सुविधानुसार खरीदारी कर सकेंगे।

**पूरी तरह तकनीक पर आधारित है लॉकर**

इस लॉकर में विशेष बात यह है कि इसमें किसी तरह की चाबी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। इस एप के जरिये खाली लॉकरों की भी जानकारी प्राप्त होगी। अगर कोई यात्री लॉकर की सुविधा लेता है तो इसमें एक छोटा व एक बड़ा लॉकर दिया गया है। हर स्टेशन पर 82 लॉकर हैं जिसमें प्रतिघंटे के लिए 20 से 30 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं, छह घंटे के लिए 60 रुपये तक का भुगतान करना होगा। साथ ही अधिकतम छह घंटे के लिए लॉकर बुक कर सकते हैं। अगर जिस समय के लिए लॉकर को बुक किया गया है, अगर उससे अतिरिक्त समय लगेगा तो कोई शुल्क नहीं देना होगा लेकिन भविष्य में इसके लिए पांच रुपये के हिसाब से समय बढ़ने के साथ भुगतान करना होगा।

**ऐसे कर सकेंगे उपयोग**

1. एप खोलकर सबसे पहले स्टेशन चुनना होगा, जिस स्टेशन पर लॉकर चाहिए।
2. कितने समय के लिए लॉकर चाहिए और तिथि का चयन करना होगा।
3. किस समय लॉकर का इस्तेमाल करना है वह बताना होगा।
4. इसका भुगतान किसी भी ऑनलाइन ई-पेमेंट एप के जरिये करना होगा।
5. लॉकर के पास जाकर फोन नंबर दर्ज करना होगा।
6. फिर ओटीपी डालना होगा, इसके बाद खुद ही लॉकर खुल जाएगा।
7. सामान निकालने के लिए लॉकर के पास जाकर दर्ज नंबर को दोबारा डालना होगा।
8. फिर लॉकर खुल जाएगा और इसके बाद यात्री सामान ले सकेंगे।

**वर्चुअल स्टोर्स यहां होंगे**

दिलशाद गार्डन, वेलकम, इंद्रलोक, राजीव चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, द्वारका मोड़, करोल बाग, बाराखंभा रोड, मयूर विहार फेज-1, नोएडा सेक्टर-52, नोएडा सेक्टर-15, नोएडा सेक्टर-59, निर्माण विहार, प्रीत विहार, वैशाली, पंजाबी बाग, पश्चिम विहार पूर्व, मूलचंद, पंजाबी बाग पश्चिम, शिवाजी स्टेडियम।

**इन स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर की सुविधा**

डिजिटल लॉकर की सुविधा फिलहाल 50 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है जिसमें पुल बंगश, पीतमपुरा, नेताजी सुभाष प्लेस, झिलमिल, तीस हजारी, शास्त्री नगर, रिठाला, शहीद स्थल (नया बस अड्डा), शाहदरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, इंद्रलोक, छतरपुर, राजीव चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर-62, नोएडा सेक्टर-18, नोएडा सिटी सेंटर, द्वारका सेक्टर-10, सुप्रीम कोर्ट, द्वारका मोड़, करोल बाग, मयूर विहार फेज-1, कौशांबी, आनंद विहार आईएसबीटी, निर्माण विहार, प्रीत विहारत, वैशाली, पीरागढ़ी, मुंडका, पश्चिम विहार पश्चिम, पंजाबी बाग, पश्चिम विहार पूर्व, मोहन इस्टेट, तुगलकाबाद, बडख्ल मोड़, गोविंदपुरी, बाटा चौक, सरिता विहार, मूलचंद, आईपी एक्सटेंशन, कड़कड़डूमा कोर्ट, पंजाबी बाग पश्चिम व शिवाजी स्टेडियम शामिल है।

# महिला आरक्षण बिल का आगामी चुनाव में कितना फ़ायदा उठा पाएगी बीजेपी

## दशकों के इंतजार के बाद महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया.

इस विधेयक का विपक्ष ने समर्थन तो किया लेकिन सरकार को कुछ मुद्दों पर कठघरे में भी खड़ा किया.

इस विधेयक में कहा गया है कि ये जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए.

साथ ही विपक्ष का कहना है परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया में समय लगेगा, ऐसे में महिला आरक्षण क़ानून के लागू होने में भी वक्त लगेगा.

परिसीमन का मतलब होता है जनसंख्या के अनुसार देश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना का निर्धारण करना. बदलती आबादी के मुताबिक़, ये एक सतत प्रक्रिया है. इसके लिए क़ानून बनाकर परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है.

महिला आरक्षण बिल के मौजूदा स्वरूप पर महुआ मोइत्रा क्या सोचती हैं?

राजनीतिक दलों और विश्लेषकों ने ये सवाल उठाया है कि जब विधेयक को लागू होने में कई वर्ष लगेंगे तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने इसे पारित क्यों कराया?

साल 2019 में हुए आम चुनाव के बाद ये बात सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया था.

ऐसे में क्या आगामी विधानसभा और आम चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है?

क्या ये महिला मतदाताओं में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश है और क्या वाकई इससे कोई असर पड़ेगा.

अगले कुछ महीनों में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं और साल 2024 में देश में आम चुनाव होंगे.

जानकारों का मानना है कि विपक्ष लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहा है कि ये बिल अगले आम चुनाव में लागू नहीं होगा. ऐसे में नारी शक्ति वंदन विधेयक इन राज्यों में बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएगा लेकिन मोदी की छवि कि 'वो करके दिखाते हैं' उसे ज़रूर मज़बूती देगा.

हालांकि बीजेपी इन चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी कि विपक्ष ने 27 साल तक ठंडे बस्ते में पड़े इस बिल पर कुछ नहीं किया और बीजेपी इसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लेकर आई है.

वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन के अनुसार महिलाओं के समक्ष बीजेपी इसे केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर पेश नहीं करेगी बल्कि एक पैकेज में इसे शामिल करके बताएगी.

राधिका रामशेषन के अनुसार, ₹अगर निर्मला सीतारमण के भाषणों को देखें तो वो केवल ताज़ा विधेयक के बारे में ही बात नहीं कर रही हैं बल्कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'उज्ज्वला योजना', 'शौचालय के निर्माण' आदि की बात कर रही हैं. ये देखा गया है कि उज्ज्वला स्कीम के बाद हुए चुनाव में महिलाओं ने जातिवाद से दूर हटकर पार्टी के लिए वोट किया है.

राधिका रामशेषन मानती हैं कि पार्टी केवल इस विधेयक को ही नहीं लेकिन इन सभी योजनाओं को एक पैकेज के तौर पर महिलाओं के सामने पेश करेगी क्योंकि केवल इस बिल से बीजेपी को कम ही फ़ायदा होगा.

हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि अब तक जो महिलाएं नरेंद्र मोदी की समर्थक रही हैं, उन पर थोड़ा असर पड़ सकता है.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, अगर ये विधेयक साल 2024 में लागू होता तो पार्टी के लिए ये गेमचेंजर साबित हो सकता था लेकिन परिसीमन और जनगणना से जोड़ना यानी इन पर काम 2026 से शुरू होगा तो ऐसे में बिल के लागू होने में समय लगेगा. वहीं ये भी बात आ रही है दक्षिण की सीट घटेगी और उत्तर की बढ़ेगी तो किस क़ानूनी पेच में फंसकर कितना लंबा खिंचेगा, ये कहना भी मुश्किल है.

जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनाव में पार्टियों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का दबाव होगा क्योंकि उन्हें ये दिखाना होगा कि वे महिला समर्थक हैं.

राधिका रामाशेषन का कहना है कि हर पार्टी को कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को टिकट तो देना ही होगा नहीं तो उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा.

साथ ही वे कहती हैं, यहां ये भी देखना होगा कि वो कैसी महिलाओं को टिकट देंगे.

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नीरजा चौधरी कहती हैं, ज़मीनी स्तर पर जो महिलाएं पंचायत या स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं, उनकी संख्या करीब 15 लाख है और वे तैयार हैं. वे अब ज़्यादा जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए सशक्त होकर अपनी बात रखती हैं. ऐसे में पार्टियों को इन महिलाओं को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में मौका देना चाहिए. नीरजा चौधरी और राधिका रामाशेषन का मानना है कि रिपोर्टिंग के दौरों पर, पहले उनके पास कई पंच पति के उदाहरण सामने आते थे लेकिन पिछले दस साल के मुक़ाबले इसमें कमी आई है.

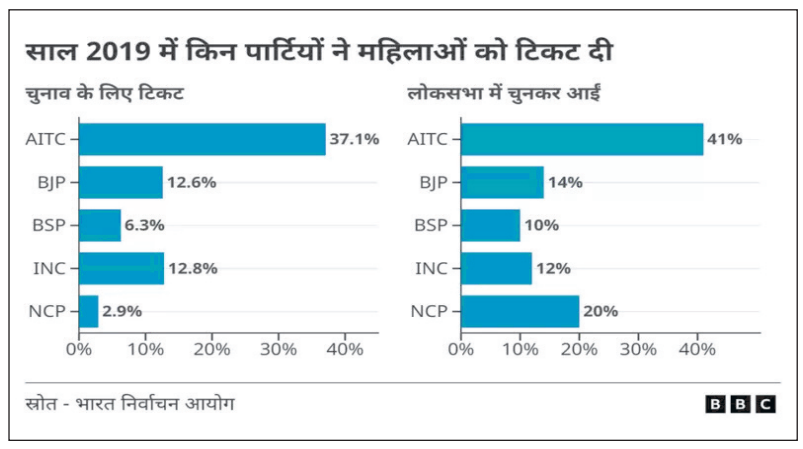


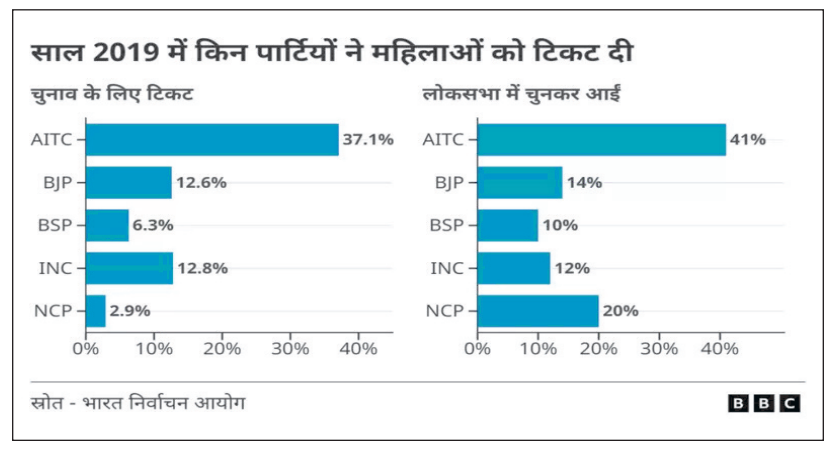


लेकिन एक पक्ष ये सवाल भी उठाता है कि अगर महिलाओं को टिकट भी दे दिया जाए तो उनका जीतना कितना सभंव हो पाएगा?

महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए बिल लोकसभा में पेश, कांग्रेस भी आई साथ

महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पर बीजेपी सांसद ने क्या कहा

उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40 फ़ीसदी टिकट देने की घोषणा की थी लेकिन पार्टी राज्य की 403 सीटों में से केवल दो ही सीट जीत पाई थी. इतना ही नहीं उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव के नतीजों से भी ख़राब रहा.

इसका जवाब देते हुए सीएसडीएम के संजय कुमार कहते हैं, ₹अगर चुनाव में पार्टी का जनाधार पूरी तरह से खिसका हुआ हो तो महिला या पुरुष को टिकट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा शोध बताता है कि महिलाओं को चुनाव खड़ा करने से महिलाएं उन्हें ज़्यादा वोट नहीं देतीं. साथ ही शोध ये भी बताता है कि लोग पार्टी को देखकर वोट करते हैं. ऐसे में यूपी में कांग्रेस के प्रति रुझान नहीं था तो वहां भी महिलाओं ने पार्टी को वोट नहीं दिया.

साल 1992 में पंचायती राज में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. उसके तीन दशक बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति में लैंगिक समानता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा सकता है.

लेकिन क्या पार्टी अगामी चुनाव में महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं, ₹बेशक उनकी पार्टी महिलाओं को ज़्यादा टिकट देगी जैसा कि यूपी में भी हुआ था लेकिन बीजेपी अगर ये सोच रही है कि उसे इस बिल के ज़रिए महिलाओं के वोट मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा.

बीबीसी ने इस बारे में बीजेपी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं मिला.

नारी शक्ति वंदन विधेयक के अनुसार, अब लोकसभा और विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यानी लोकसभा में 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक़, साल 2019 के आम चुनाव में 8,054 उम्मीदवारों में से 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था.

जिसका मतलब ये हुआ कि केवल 9 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया गया था हालांकि 2014 में 8,251 में से 668 महिलाओं को टिकट दिया गया था.

सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बीजेपी ने साल 2019 में 12.5 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिए, वहीं कांग्रेस ने 12.8 प्रतिशत महिलाओं को मैदान में उतारा था. भारतीय न्याय संहिता पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के ख़िलाफ़ रेप और मैरिटल रेप के मामलों को कैसे प्रभावित करेगी

तृणमूल कांग्रेस ने 37 प्रतिशत, तमिलनाडु की पार्टी एनटीके ने 47 प्रतिशत टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए थे.

एक अनुमान के अनुसार भारत की राजनीति में ओबीसी का वोट बैंक तकरीबन 45 फ़ीसद है. ऐसे में विपक्ष की ओबीसी, मुसलमान महिलाओं को शामिल करने की मांग का क्या असर पड़ेगा?

इसका जवाब देते हुए संजय कुमार कहते हैं, ₹अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं को तो लाभ मिलेगा लेकिन ओबीसी महिलाएं इससे ज़रूर वंचित रह जाएगी. ओबीसी समुदाय के कुछ वोटरों का झुकाव विपक्ष की ओर झुकेगा क्योंकि वो इसे जोर-शोर से उठा रहे हैं. ऐसे में ओबीसी महिलाओं में, वोट बीजेपी से खिसकता हुआ नज़र आ सकता है.₹

महिला आरक्षण बिल का इतिहास

महिला आरक्षण

साल 1996 में महिला आरक्षण बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने संसद में पेश किया था.

ये बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रुप में पेश हुआ था लेकिन पारित नहीं हो सका.

इस बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी आरक्षण का प्रस्ताव दिया था.

इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान था लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं था.

साल 1998 में अटल बिहारी वाजेपयी की सरकार ने लोकसभा में फिर बिल पेश किया हालांकि पार्टियों के विरोध के कारण ये बिल पारित नहीं हो सका.

वाजपेयी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को 1999,2002, और 2003-2004 में भी पारित कराने की कोशिश की.

बॉम्ब सक्वॉड, ये यूनिट हर एक देश की सेना में होती है और अमूमन इस दस्ते में पुरुष होते हैं.

साल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी. इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बिल को साल 2008 में राज्यसभा में पेश किया और 2010 में ये भारी बहुमत से पारित हुआ.

इस बिल के समर्थन में बीजेपी, वाम दल और जेडीयू आए लेकिन जब लोकसभा में पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया जो यूपीए का हिस्सा थे.

कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार ख़तरे में पड़ सकती है. साल में 2008 में इस बिल को क़ानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था. इसके दो सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे.

इन दोनों ने कहा कि वे बिल के विरोधी नहीं है लेकिन महिलाओं को 20 फ़ीसदी टिकट और महिला आरक्षण 20 फ़ीसदी से अधिक न होने की की बात कही गई. साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप ख़त्म हो गया.

साल 1998-99, 2004 और 2009 से तुलना की जाए तो 2019 में बीजेपी को महिला वोटरों का फायदा मिला था लेकिन इन चुनाव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का असर महिला मतदाताओं पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी.

**मिलते-जुलते मुद्दे**

महिलाएँ
संसद
कांग्रेस पार्टी
भारत
महिला अधिकार
महिला आरक्षण विधेयक।

# चुनावी समर में किस्मत आजमा रही महिलाएं, चुनाव प्रबंधन पति और स्वजनों के हवाले

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खंडवा जिले की पंधाना और खंडवा विधानसभा में महिला प्रत्याशी किस्मत आजमा रही है। इनमें दो भाजपा और एक को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। नारी सशक्तिकरण की दुहाई देकर इन्हे टिकिट दिलवाने की भागमभाग से लेकर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ही नहीं इनके नाम पर वोट मांगने के लिए भी पति और स्वजन जनसंपर्क कर रहे है।

चुनाव के लिए पार्टी की ओर से चुनाव संचालक और रणनीतिकार भी तैनात किए गए है लेकिन पूरी कमान पति, भाई, पिता और गाड फादर के हाथों में होने से चुनावी रण में प्रत्याशी का वजूद चेहरे तक की सिमट कर रह गया है।

खंडवा जिले में पंधाना सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को टिकिट दिया है। दोनों महिलाएं पूर्व में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन दोनों की राजनीतिक भूमिका बदल गई है। भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे करीब दो माह पूर्व कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई थीं। पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ी थी। जबकि इस बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में है।

**पार्टी नेताओं के साथ ही स्वजन भी है सक्रिय**

चुनावी समर में किस्मत आजमा रही महिलाएं, चुनाव प्रबंधन पति और स्वजनों के हवालेMP Election 2023: चुनावी समर में किस्मत आजमा रही महिलाएं, चुनाव प्रबंधन पति और स्वजनों के हवाले

पंधाना विधानसभा में भाजपा ने चुनाव की कमान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर को सौंपी है। वहीं सुखदेव पटेल और जितेंद्र मंडलोई के मार्गदर्शन में चुनावी गतिविधियां पार्टी स्तर पर संचालित हो रही है। इसके समानातंर प्रत्याशी छाया मोरे के पति बैंककर्मी गोविंद मोरे तथा सलाहकार जायसवाल बंधु चुनावी मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मूलतः खरगोन जिले की होने से क्षेत्र के लोग भी चुनाव प्रचार में योगदान दे रहे है।

**वरिष्ठ नेता संभाल रहे कमान**

कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी रूपाली बारे ने पिछला चुनाव कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय की हैसियत से लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। इनके पिता नंदू बारे पहले दो बार यहां से कांग्रेस के टिकिट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उनके निधन के बाद पिछले चुनाव में रूपाली ने पिता की जगह कांग्रेस से टिकिट मांगा था लेकिन टिकिट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था।

चुनाव में समाजसेवी मधुभाई पटेल ने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था। वहीं इस बार वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में है। इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से संचालन वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल कुमार जैन और अभिकर्ता सुरेश कनाड़े दायित्व निभा रहे है। प्रत्याशी की रणनीतिकारों में स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी नामदेव सक्रिय है।

**प्रत्याशी पत्नी की जगह स्वयं मांग रहे वोट**

खंड़वा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कंचन तनवे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। कोई छह माह पूर्व वे भाजपा से अधिकृत नहीं करने पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव निर्दलीय की हैसियत से लड़ चुकी है। चुनाव की पूरी रणनीति और संचालन उनके पति मुकेश तनवे ने संभाला था। सदस्य का चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भी उनकी महत्ती भूमिका रही।

वे पंधाना तहसील में भाजपा संगठन में जिला महामंत्री और अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष के अलावा बलाही समाज में भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। उनका यह अनुभव विधानसभा चुनाव में भी पत्नी कंचन तनवे के काम आ रहा है।

भाजपा संगठन के अलावा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मंत्री विजय शाह, महापौर अमृता अमर यादव चुनावी समर में उनके साथ नजर आ रहे है। इसके बावजूद चुनावी कमान पति मुकेश तनवे संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं चुनाव प्रचार में प्रत्याशी पत्नी की जगह स्वयं घर-घर पहुंच कर वोट मांग रहे हैं।

# पांच चुनाव में BJP ने 110, कांग्रेस ने 104 महिलाओं को टिकट दिए, क्या इस बार बढ़ाएंगे हिस्सेदारी?

राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी यह काफी कम है। 1952 में हुए पहले चुनाव में प्रदेश में सिर्फ दो महिलाएं ही विधायक बनीं थी। 1985 के चुनाव में पहली बार 17 महिलाएं विधायक चुनी गईं। अभी यहां महिला विधायकों की संख्या 27 है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के नाम से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर बहस तेज हो गई। भाजपा-कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रही हैं। राजस्थान विधानसभा के पिछले पांच चुनाव के आंकड़े देखें तो भाजपा ने 110 महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने 104 महिलाओं को टिकट दिए।

2003 के बाद पहली बार भाजपा ने 2018 में कांग्रेस से कम महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। इस दौरान कांग्रेस ने 27 तो भाजपा ने 23 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा था। इससे पहले 2013 में भाजपा ने 26, कांग्रेस ने 24, 2008 में भाजपा ने 31, कांग्रेस ने 23, 2003 में भाजपा ने 22, कांग्रेस ने 18 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। 1998 में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने आठ महिलाओं को पार्टी का टिकट दिया था।

**महिलाओं का विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन ये काफी कम**

राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी यह काफी कम है। वर्तमान में प्रदेश में सिर्फ 27 महिला विधायक हैं। हालांकि, 1952 में हुए पहले चुनाव में प्रदेश में सिर्फ दो महिलाएं यशोदा देवी और कमला बेनीवाल ही विधायक बनीं थी। शुरुआती चुनाव में महिला विधायकों की संख्या इकाई में ही गिनी जाती रही। 1985 के चुनाव में पहली बार 17 महिलाएं विधायक चुनी गईं। इसके बाद 2008 में 28 महिलाएं विधायक बनी और यही आंकड़ा 2013 के चुनाव में भी कायम रहा। लेकिन, 2018 के चुनाव में यह आंकड़ा एक फिर नीचे आया गया।

**महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन नहीं मिले जनता केवोट**

राजस्थान विधानसभा चुनाव के पिछले पांच साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 696 महिलाओं ने चुनाव लड़ा जिसमें से 458 की जमानत जब्त हो गई। इससे साफ है कि महिलाओं ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दिए। देखें पांच साल के आंकड़े...

1998 का विधानसभा चुनाव 69 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, इनमें से 44 की जमानत जब्त हो गई थी। 14 महिलाएं विधायक बनीं।

2003 में 118 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन 76 की जमानत जब्त हो गई। 12 महिलाएं ही विधायक चुनी गईं।

2008 का विधानसभा चुनाव 154 महिलाओं ने लड़ा, इनमें से 95 की जमानत जब्त हो गई। 28 महिलाएं विधायक बनकर विधानसभा पहुंची।

2013 का विधानसभा चुनाव 166 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, इनमें 105 की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ महिलाएं ही 28 विधायक बन सकीं।

2018 के चुनावी मैदान में 189 महिलाएं उतरी, लेकिन 138 की जमानत जब्त हो गई। 27 महिलाएं विधायक बनकर विधानसभा पहुंची।

**अब हर पार्टी को कम से कम से 66 महिलाओं को देने पड़ेंगे टिकट**

राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। पिछले पांच साल के आंकड़े पर नजर डालें तो प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर भी 200 महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती हैं। 2018 में सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलाकर 189 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। लेकिन, महिला आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद प्रदेश की सभी पार्टियों को कम से कम 66 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने ही पड़ेंगे।

**महिला आरक्षण बिल का ये होगा असर**

राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। महिला आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद यहां महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 66 हो जाएगी। इसी तरह लोकसभा की आठ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

# 'शराब घोटाले के किंगपिन हैं केजरीवाल, जांच से क्यों भाग रहे कट्टर ईमानदार ?', भाजपा ने दिल्ली सीएम से पूछे तीखे सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

संबित पात्रा ने कहा कि अभी तीन दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है। उससे सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित होता है। केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है।

**नई दिल्ली।** दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गुरुवार को बुलाया था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने लेटर लिखकर ईडी को अपना जवाब भेजा है। इसे लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है।

**ईडी के प्रश्नों का जवाब देने से भाग रहे हैं दिल्ली सीएम- BJP**

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के प्रश्नों का जवाब देने व सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। ईडी के सामने पेश नहीं होकर उन्होंने आबकारी घोटाला में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। यदि वह भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो डर क्यों रहे हैं? वह आबकारी घोटाला के किंगपिन हैं, इसलिए बच नहीं सकते हैं।

दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी!

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच एजेंसियों, अपने लोगों, चुनाव प्रणाली, कानून किसी पर विश्वास नहीं है। तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जमानत याचिका नामंजूर करते हुए जिस तरह से टिप्पणी की है उससे स्पष्ट होता है कि आबकारी घोटाले में 338 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ईडी को लिखे पत्र में पूछा है कि उन्हें व्यक्तिगत या मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक किस हैसियत से पूछताछ लिए बुलाया गया है? इस तरह के प्रश्न करने की जगह उन्हें बताना चाहिए कि क्या वह कानून से ऊपर हैं या भगवान हैं कि उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है। वह भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

**मनोज तिवारी को कैसे पता ED करेगी गिरफ्तार?- सीएम केजरीवाल**

केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि सांसद मनोज तिवारी को कैसे पता चला कि ईडी ने उन्हें समन भेजा है और उनकी गिरफ्तारी होगी। इस तरह के प्रश्न उठाने की जगह उन्हें बताना चाहिए वह सिसोदिया व संजय सिंह की गिरफ्तारी होने की बात किस आधार पर करते थे?

क्या उन्होंने ईडी को सिसोदिया को गिरफ्तार करने की बात कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा है। इस कारण ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जांच में असहयोग कर वह मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दीपावली व पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात कर पूछताछ में शामिल नहीं होने की बात कर रहे हैं। फिर तो उनसे कभी पूछताछ नहीं हो सकती है क्योंकि आने वाले समय में कई त्योहार और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। पहले चंद कागज के टुकड़े लेकर नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले केजरीवाल अब जांच एजेंसी के समन को गलत बता रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आबकारी नीति में शराब ठेकेदारों का कमीशन बढ़ाने, आबकारी विभाग की समिति की सिफारिश के बावजूद थोक कारोबार निजी हाथ में देने, कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपये माफ करने, शराब बनाने वाली कंपनियों को खुदरा कारोबार में अनुमति देने, एयरपोर्ट पर ठेका नहीं खुलने पर ठेकेदार को जमानत राशि वापस देने और नई आबकारी नीति वापस लेने का कारण बताने को कहा।

## भाजपा ईडी को चला रही है : गोपाल राय

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने प्रेसवार्ता कर कहा कि भाजपा ईडी को चला रही है।उन्होंने कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा और केजरीवाल ने उस नोटिस का जवाब ईडी को दे दिया कि आप का नोटिस स्पष्ट नहीं है। उसमें उन्होंने कई सवाल उठाया। मगर उस पर ईडी का जवाब नहीं आया उस पर भाजपा का जवाब आया।

उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब देने के लिए आए। इससे साफ है कि भाजपा ही तय करती है कि ईडी को कब किसे और क्या नोटिस भेजना है। उन्होंने कहा कि भाजपा आप को समाप्त करना चाहती है आप उनकी कैबिनेट के मंत्री राजकुमार आनंद के यहां ईडी ने छापा मारा है।जबकि उनके खिलाफ कोई, मुकदमा नहीं, कोई नोटिस नहीं है, मगर छापा पड़ गया है।

## दमघोंटू की ओर बढ़ रही दिल्ली की हवा: गंभीर स्तर पर पहुंची दिल्ली की हवा, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

**नई दिल्ली।** राजधानी में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु दमघोंटू की ओर रुख कर रही है। गुरुवार को एक बार फिर एनसीआर में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सफर इंडिया के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 343 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। वहीं, नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 397 है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 364 दर्ज किया गया। यह इस सीजन का सर्वाधिक एक्यूआई है और यह लगातार पांचवां दिन रहा जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रही, जबकि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को वायु सूचकांक में पांच अंक की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, न्यू मोती बाग व आनंद विहार समेत सात इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी व 27 इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित रहा। दिल्ली की हवा समग्र रूप से खराब श्रेणी में बनी रही। जैसे-जैसे हवा गंभीर श्रेणी की ओर रुख कर रही है वैसे-वैसे ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने की आशंका बढ़ रही है।

**न्यू मोती बाग व मुंडका सर्वाधिक प्रदूषित**

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को 27 इलाकों में बेहद खराब हवा दर्ज की गई। इसमें न्यू मोती बाग व मुंडका में सर्वाधिक वायु सूचकांक दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 428 व 417 रहा। वहीं, पूसा, आनंद विहार व आया नगर में 416, पंजाबी बाग में 407, वजीरपुर में 408 वायु सूचकांक दर्ज किया गया। इसके अलावा नेहरू नगर में 395, श्री अरविंदो मार्ग में 392, रोहिणी में 385, शादीपुर में 381 व पटपड़गंज में 380 समेत 27 इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया।

**शुक्रवार तक बेहद खराब श्रेणी में रहेगी हवा**

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मुताबिक बुधवार को हवाएं उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर से चलीं। इस दौरान हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रतिघंटा रही। बृहस्पतिवार को हवाएं पूर्व व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 4 से 12 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी। वहीं, सुबह के समय हल्की धुंध छाएगी। ऐसे में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं, शुक्रवार को हवाएं दक्षिण-पूर्व व उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से चलेंगी। हवा की चाल 4 से 8 किलोमीटर प्रतिघंटे रहने का अनुमान है। सफर इंडिया के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में पीएम 2.5 की मात्रा लगभग 176 दर्ज की गई, जोकि बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं, पीएम 10 की मात्रा करीब 326 दर्ज की गई, जो कि गंभीर स्तर है।

**ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषित रही हवा**

सीपीसीबी के अनुसार बुधवार को एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा का सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 354 रहा, जोकि बेहद खराब श्रेणी है। फरीदाबाद में 309, गाजियाबाद में 254, नोएडा में 312 व गुरुग्राम में 226 एक्यूआई दर्ज किया गया।

## पटाखे की डिलीवरी कर रहा था दिल्ली मेट्रो का कर्मचारी, घर पर जमा कर रखी थी बड़ी खेप; गिरफ्तारी के बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली मेट्रो के एक अस्थायी कर्मचारी को पटाखे की डिलीवरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 20 किलो से अधिक का विस्फोटक जब्त किया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कम समय में अधिक कमाई करना चाहता था इस कारण वह गाजियाबाद और गुरुग्राम से पटाखे की डिलीवरी दिल्ली में करता था।

**पूर्वी दिल्ली।** मेट्रो का एक कर्मचारी राजधानी दिल्ली में पटाखे की अवैध डिलीवरी करते पाया गया है। जिले के मंडावली थाना पुलिस ने पटाखे की डिलीवरी करने वाले मेट्रो के एक अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिव्यांशु के तौर पर हुई है। पुलिस ने इसके घर से 20.900 किलो पटाखे बरामद किए हैं। मंडावली थाना पुलिस ने सरकारी आदेश के उल्लंघन और विस्फोटक पदार्थ बेचने की धारा में प्राथमिकी दर्कीज है।

जिला पुलिस पुलिस उपायुक्त अमृता गुगुलोथ ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पांडव नगर इलाके में एक शख्स चोरी छिपे पटाखे बेच रहा है। हेड कांस्टेबल योगेश, मनोज और कांस्टेबल अनिता की एक टीम बनाई गई। टीम ने एक घर पर छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया।

**जल्द अमीर बनना चाहता था आरोपी**

आरोपी के घर से पुलिस को पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मेट्रो में अस्थायी कर्मचारी है और जल्द रुपये कमाने के लिए वह अधिक कीमत पर पटाखे भी बेच रहा था। वह गाजियाबाद और गुरुग्राम से पटाखे खरीदकर लाता था और दिल्ली में ग्राहकों की मांग के अनुसार डिलीवरी करता था।

## थैलेसीमिया के मरीजों को बड़ी राहत, 45 की जगह आठ मिनट में पता चल रहा दिल में कितना आयरन

थैलेसीमिया के मरीजों को हमेशा खून चढ़ाने की जरूरत होती है। इस दौरान आयरन की अधिकता हो जाती है, जो दिल के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में जमा हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए पहले हृदय की सामान्य एमआरआइ होती थी जिसमें पहले करीब 45 मिनट समय लगता था।

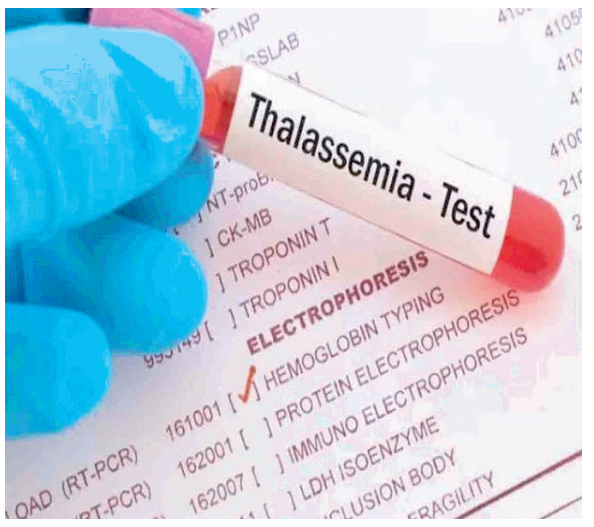


**नई दिल्ली।** थैलेसीमिया के मरीजों के दिल में जमा होने वाले आयरन का पता महज आठ मिनट में चल जाता है। एम्स ने इसकी जांच के लिए रैपिड एमआरआई तकनीक की शुरूआत की है।

एम्स में हर दिन इस तकनीक की मदद से करीब 50 मरीजों की जांच होती है। दरअसल थैलेसीमिया के मरीजों को हमेशा खून चढ़ाने की जरूरत होती है। इस दौरान आयरन की अधिकता हो जाती है, जो दिल के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में जमा हो जाती है। इसका पता लगाने के लिए पहले हृदय की सामान्य एमआरआइ होती थी जिसमें करीब 45 मिनट समय लगता था। इसे देखते हुए एम्स दिल्ली ने सिर्फ आठ मिनट के समय में दिल की जांच करने वाली रैपिड एमआरआई तकनीक को शुरू किया। इसकी मदद से सटीक जानकारी मिल रही है। यूके में इस तकनीक ने थैलेसीमिया से मौत के 80 फीसदी मामले कम किए।

बुधवार को एम्स में प्रेस वार्ता के दौरान कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलाजी की विभागाध्यक्ष डा. प्रिया जागिया ने कहा कि इस तकनीक को अपनाकर यूनाइटेड किंगडम (यूके) थैलेसीमिया मरीजों की मौतें 80 प्रतिशत कम करने में कामयाब रहा है। इस वजह से यूके में थैलेसीमिया मरीजों की औसत उम्र 40 वर्ष होती है जबकि भारत में थैलेसीमिया मरीजों की औसत उम्र 25 वर्ष होती है। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया और स्किल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों को बार-बार खून चढ़ाए जाने से शरीर में आयरल लोड बढ़ जाता है, जो लिवर, हृदय व पैंक्रियाज सहित अन्य अंगों पर प्रभाव डालता है। ऐसे में देखा गया है कि थैलेसीमिया के 50 से 70 फीसदी मरीजों का हृदय खराब होने या हृदय में आयरन जमा होने से मौत हो जाती है। इससे बचाव के लिए मरीजों के शरीर से आयरन लोड को कम करना होता है। नई एमआरआई तकनीक सिर्फ आठ मिनट में जांच कर नतीजे बता देगी।

## डीयू की छात्राओं से बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, महिलाएं संसद और देश के आर्थिक विकास की रीढ़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा और विधानसभाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

**नई दिल्ली।** दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्राओं को संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि महिलाएं संसद और देश के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा और विधानसभाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी। कॉलेज की प्लैटिनम जयंती के अवसर पर भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने 21 सितंबर को इतिहास रचा जब महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। जो अब एक कानून बन गया है।

नए संसद भवन के साथ महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि नए भवन में 21 सितंबर को संसद के एक विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से इतिहास बन गया। वह दिन हिंदू तिथि के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ मेल खाता था। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि महिलाएं संसद और हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ हैं।

नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं।

# ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, बोले- नोटिस अवैध और राजनीतिक; ये मुझे रोकने की कोशिश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन पर कहा कि ये नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। फिलहाल, केजरीवाल मध्य प्रदेश में पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं।

**नई दिल्ली।** दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया। जिसके बाद उन्हें आज दो नवंबर को ईडी कार्यालय में पेश होना था। लेकिन धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सीएम नहीं पहुंचे। बयान के बाद मुख्यमंत्री पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। उन्होंने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है।

**आज पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस भाजपा के इशारे पर भेजा गया है। नोटिस यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि आप का राष्ट्रीय संयोजक और एक स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और आप के अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं, जिनके लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है।

**सीएम के ईडी ऑफिस में पेश न होने पर क्या बोले संबित पात्रा**

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए जवाब पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आखिर क्या कारण अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्द ही समाप्त हो इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दी जाए। इसका मतलब जांच एजेंसी केजरीवाल से पूछताछ ही न करे। क्योंकि कभी होली है तो कभी दीवाली है। इससे साफ लगता है कि चोरी हुई है।

**विधानसभा चुवान के प्रचार में व्यस्त हैं मुख्यमंत्री**

जानकारी के लिए बता दें कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आज ही उन्हें ईडी कार्यालय में पेश होना था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। इसके अलावा 5 नवंबर को हरियाणा में सीएम का कार्यक्रम है। ऐसे में व्यस्त कार्यक्रम की वजह के सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं।

**क्या ईडी की चार्जशीट में है अरविंद केजरीवाल का नाम**

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। ईडी ने दावा किया कि आबकारी नीति आप के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी, ताकि लगातार अवैध धन कमा कर खुद तक पहुंचाया जा सके।

# मौसम में बदलाव के बावजूद डेंगू का कहर जारी, अब तक मिल चुके हैं करीब 1100 मरीज

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के अलग-अलग अस्पतालों में रोजाना 5 मरीजों की डेंगू जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। डेंगू नियंत्रण एवं स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी सीएमओ कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब तक करीब 1100 मरीज मिल चुके हैं और 100 से अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।

**गाजियाबाद।** मौसम में ठंडक होने के बावजूद जिले में डेंगू का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक करीब 1100 मरीज मिल चुके हैं और 100 से अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।

**डेंगू से आठ लोगों की मौत**

इतना ही नहीं आठ लोगों की डेंगू से मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग का दस्तक अभियान तेज नहीं हुआ है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में प्रतिदिन बुखार के 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी में बुखार के गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है।

**रोजाना 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट आ रही डेंगू पॉजिटिव**

प्रतिदिन 5 मरीजों की डेंगू जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। डेंगू नियंत्रण एवं स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी सीएमओ कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पता चला है कि लोनी मुरादनगर मोदीनगर भोजपुर और डासना में अभी तक नोडल अधिकारियों का दौरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही जिला पब्लिक हेल्थ लैब में डेंगू की जांच रिपोर्ट 3 दिन से पहले नहीं मिल रही है।

**24 घंटे खुल रही है लैब**

यह स्थिति तब है कि जबकि लैब 24 घंटे खुल रही है। मलेरिया विभाग की टीम भी कुछ खास इलाकों में जाकर सर्वे के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर रही है। अधिकारियों एवं शिकायत करने वाले लोगों के घर जाकर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।

## तेंदुआ ले उड़ा पिंजरा, जांच घेरे में फंसे उप क्षेत्रीय वन अधिकारी

गाजियाबाद में पिछले तीन साल से बार-बार तेंदुआ आ रहा है। इसको लेकर सामाजिक वानिकी प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्क रहते हैं। चर्चा है कि कहीं पिंजरे को तेंदुआ तो नहीं ले उड़ा। जानकारी के अनुसार सदरपुर गांव के जंगलों में 12 जून 2022 को तेंदुआ दिखाई देने की शिकायत पर वन विभाग ने जंगलों में पिंजरा लगा दिया।

**गाजियाबाद।** तेंदुआ को पकड़ने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पसीना निकल जाता है, लेकिन पहली बार तेंदुए को कैद करने के लिए लगाया गया भारी-भरकम पिंजरा जंगलों से गायब होने पर अधिकारियों की नींद उड़ गई है। चर्चा है कि कहीं पिंजरे को तेंदुआ तो नहीं ले उड़ा। जानकारी के अनुसार सदरपुर गांव के जंगलों में 12 जून 2022 को तेंदुआ दिखाई देने की शिकायत पर वन विभाग ने जंगलों में पिंजरा लगा दिया। विभाग से यह पिंजरा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहसिंह को आवंटित किया गया था।

**वन विभाग गौतमबुद्ध नगर ने भी की पिंजरे की मांग**

चार जनवरी 2023 को वन विभाग गौतमबुद्ध नगर ने तेंदुआ दिखने पर पिंजरे की मांग की। सदरपुर से पिंजरा लाकर गौतमबुद्ध नगर को भेजने के निर्देश जारी किए गए लेकिन स्थलीय निरीक्षण के दौरान पिंजरा वहां से गायब मिला। 20 दिन तक दिन-रात पिंजरे को तीन टीमों ने तलाश किया, लेकिन पिंजरा नहीं मिला। इस प्रकरण के लिए जांच समिति गठित कर दी गई। समिति ने जांच में पाया कि उप क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहसिंह ने राजकीय सामग्री की सुरक्षा में लापरवाही बरती है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित को नोटिस जारी करके जवाब मांग गया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। अब प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी मनीष सिंह ने जांच रिपोर्ट के आधार पर पिंजरे की कीमत 99 हजार रुपये वेतन से वसूलने के आदेश जारी कर दिये हैं।

गायब हुए पिंजरे में दो बार तेंदुआ कैद किया जा चुका है। गाजियाबाद में पिछले तीन साल से बार-बार तेंदुआ आ रहा है। इसको लेकर सामाजिक वानिकी प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्क रहते हैं। वायुसेना अधिकारियों के अनुरोध पर वायु सेना स्टेशन हिंडन के जंगलों में भी पिंजरा लगाया जाना है।

वन विभाग के पास दो पिंजरा हैं। 43 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं।

## दीपावली की आतिशबाजी से बिगड़ेगी शहर की हवा, जमकर बिक रहे हैं पटाखे

शहर में गाडौली कादीपुर और फरुखनगर क्षेत्र के डाबोदा में बड़े पटाखा गोदाम बने हुए हैं। पिछले अगर छह वर्षों की बात करें तो 2016 से 2022 तक दीपावली की रात और इसके अगले दिन सुबह दम घोंटने वाला प्रदूषण रहा। स्माग होने के कारण त्योहार के बाद के दिनों तक लोगों को सिर दर्द आंखों में जलन जैसी शिकायतें रही।

**गुरुग्राम।** नवंबर की शुरुआत के साथ ही शहर की हवा सांस लेने लायक नहीं है। इन दिनों शहर का एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 200 से 300 के बीच दर्ज किया जा रहा है।

**पटाखा गोदामों से हो रही पटाखों की बिक्री**

गुरुग्राम में सुबह एक्यूआइ 298 और मानेसर में 250 रहा। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के बाद एक्यूआइ और ज्यादा बिगड़ेगा। दीपावली से पहले ही शहर के पटाखा गोदामों से पटाखों की बिक्री हो चुकी है।

शहर में गाडौली, कादीपुर और फरुखनगर क्षेत्र के डाबोदा में बड़े पटाखा गोदाम बने हुए हैं। पिछले अगर छह वर्षों की बात करें तो 2016 से 2022 तक दीपावली की रात और इसके अगले दिन सुबह दम घोंटने वाला प्रदूषण रहा। स्माग होने के कारण त्योहार के बाद के दिनों तक लोगों को सिर दर्द, आंखों में जलन जैसी शिकायतें रही।

दीपावली से पहले भी अब सड़कों पर वाहनों के ट्रैफिक दबाव, नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण लगे कूड़े के ढेरो में आग लगाने आदि कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है। तापमान में गिरावट, नमी होने तथा हवा नहीं चलने के कारण प्रदूषण नहीं छंट रहा और सुबह के समय एक्यूआइ सबसे ज्यादा खराब रहता है।

**दीपावली पर पिछले नौ साल में यह रहा AQI**

वर्ष - एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स)
2013 - 221
2014 - 195
2015- 170
2016- 500
2017- 420
2018 - 972
2019 - 985 (दीपावली की आधी रात के बाद)

# NH-9 बना गाजियाबाद में क्राइम का नया हॉट स्पॉट, लगातार वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती

परिवहन विशेष न्यूज

एनएच-नौ क्राइम का नया हॉट स्पॉट बन गया है। यहां पर लूट से लेकर हत्या तक की वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं पुलिस इस नेशनल हाइवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रही है। हालांकि दिन और रात के वक्त यहां पर सिटी क्षेत्र में विजयनगर से कविनगर के बीच आठ बाइक पीआरवी की ड्यूटी लगाई है।

**गाजियाबाद।** गाजियाबाद में एनएच-नौ क्राइम का नया हॉट स्पॉट बन गया है। यहां पर लूट से लेकर हत्या तक की वारदात को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, पुलिस इस नेशनल हाइवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रही है, जबकि हाइवे पर पुलिस की पीआरवी गश्त भी करती है।

**बढ़ाई गई पुलिसबल की संख्या**

सुरेंद्र नागर की हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी, इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है।

रात ही नहीं दिन में भी यहां पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर बदमाश कमिश्नरेट पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। यही वजह है कि अब एनएच-नौ पर वारदातों को रोकने के लिए पुलिसबल की संख्या बढ़ाई गई है, नए चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं।

**वारदात एक**

अगस्त माह में गाजीपुर से डासना जा रहे पशु स्कूटी सवार व्यापारी नदीम से एनएच-नौ पर 23.41 लाख रुपये की लूट की वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर अंजाम दिया।

बदमाशों ने एनएच-नौ पर नदीम का पीछा कर लूट की वारदात की, लेकिन तमंचा लेकर चल रहे बदमाशों को पुलिस की टीम ने एक भी चेकिंग प्वाइंट पर नहीं पकड़ा था।

**वारदात दो**

एबीईएस कालेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हापुड़ की छात्रा कीर्ति सिंह से डासना में एनएच-नौ पर 27 अक्टूबर को उस वक्त बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात की, जब वह आटो में बैठकर कालेज से अपने घर जा रही थी।

झपटमारों ने मोबाइल लूट का विरोध करने पर कीर्ति सिंह को आटो से धक्का दे दिया था, वह गंभीर रूप से जख्मी हुई और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वारदात से गाजियाबाद कमिश्नरेट में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए।

**वारदात तीन**

जनवरी 2020 में एक कंपनी में कार्यरत रिसर्च एनालिस्ट कात्यायनी से आटो सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, विरोध करने पर उनको चलते आटो से नीचे धक्का दे दिया गया था। बदमाशों ने पीड़िता से पर्स, मोबाइल व अंगूठी लूट की वारदात की थी, इस मामले में मसूरी थाने में तहरीर दी गई थी, इसके बाद भी आटो सवार बदमाशों का आतंक एनएच- नौ पर अब तक जारी है।

**वारदात चार**

बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक आटो पार्टस कंपनी के जीएम योगेंद्र तनेजा से जुलाई 2021 में एनएच- नौ पर बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

वारदात के वक्त योगेंद्र कार में सवार थे, लुटेरों ने कार से तेल रिसने की बात कह उनको रोका था। उनके रुकते ही कार के अंदर रखा बैग लूट कर बदमाश वहां से भाग गए थे। यह वारदात एबीईएस कट के पास हुई थी।

एनएच- नौ पर लूट की वारदात को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। दिन और रात के वक्त यहां पर सिटी क्षेत्र में विजयनगर से कविनगर के बीच आठ बाइक पीआरवी की ड्यूटी लगाई है, इसके साथ ही आठ चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं, जिससे कि संदिग्धों की पहचान कर उनको गिरफ्तार कर वारदात होने से रोकी जा सके।

**- निमिष पाटिल, एसीपी कोतवाली**

# दुर्घटनाओं के आंकड़े सड़क सुरक्षा नियमों की विफलता को दर्शा रहे हैं

**ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर आम आदमी में संवेदनहीनता की काली छाया का पसरना त्रासद है और इससे भी बड़ी त्रासदी सरकार की आंखों पर काली पट्टी का बंधना है। हर स्थिति में मनुष्य जीवन ही दांव पर लग रहा है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है?**

ललित गर्ग

सड़क हादसों पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की डरावनी, चिन्ताजनक एवं भयावह रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक, पिछले साल 4.61 लाख सड़क हादसे हुए। इन दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों ने जान गंवाई। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि तकरीबन हर एक घंटे में 53 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। हर घंटे इनमें 19 लोगों की मौत हुई। हादसों एवं लापरवाही की खूनी होती सड़कें चिन्ता का बड़ा सबब हैं। सड़कों की 'दुर्घटनाओं' के कुछ दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं, जो भयावह होते हैं, त्रासद होते हैं, डरावने होते हैं। सच यह है कि बेलगाम वाहनों एवं यातायात कानूनों एवं नियमों की अवहेलना की वजह से सड़कें अब पूरी तरह असुरक्षित हो चुकी हैं। सड़क पर तेज गति से चलते वाहन एक तरह से हत्या के हथियार होते जा रहे हैं। उक्त रपट यह भी बताती है कि सड़क हादसों की संख्या में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनसे होने वाली मृत्यु की दर 9.4 प्रतिशत बढ़ी। इसी तरह सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एक्सप्रेसवे हाईवे और राजमार्गों पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने का ही काम करती है लेकिन न तो वाहन चालक अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार हैं और न ही सरकारें एवं यातायात पुलिस। बीते वर्ष सड़क हादसों में 66 हजार से अधिक लोगों ने इसलिए जान गंवाई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी या फिर हेलमेट नहीं लगाया था। यह विडम्बनापूर्ण है कि हर रोज ऐसी दुर्घटनाओं और उनके भयावह नतीजों की खबरें आम होने के बावजूद बाकी वाहनों के मालिक या चालक कोई सबक नहीं लेते। सड़क पर दौड़ती गाड़ी मामूली गलती से भी न केवल दूसरों की जान ले सकती है, बल्कि खुद चालक और उसमें बैठे लोगों की जिंदगी भी खत्म हो सकती है। पर लगता है कि सड़कों पर बेलगाम गाड़ी चलाना कुछ लोगों के लिए मौज-मस्ती एवं शौक का मामला होता है लेकिन यह कैसी मौज-मस्ती है जो कई जिन्दगियां तबाह कर देती है। ऐसी दुर्घटनाओं को लेकर आम आदमी में संवेदनहीनता की काली छाया का पसरना त्रासद है और इससे भी बड़ी त्रासदी सरकार की आंखों पर काली पट्टी का बंधना है। हर स्थिति में मनुष्य जीवन ही दांव पर लग रहा है। इन बढ़ती दुर्घटनाओं की नृशंस चुनौतियों का क्या अंत है? बहुत कठिन है दुर्घटनाओं की उफनती नदी में जीवनरूपी नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना, यह चुनौती सरकार के सम्मुख तो है ही, आम जनता भी इससे बच नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 तक देश में दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौत की संख्या को आधा करने का लक्ष्य रखा है, जो एक उम्मीद जगाता है एवं रोशनी बन रहा है।

दुनिया में सर्वाधिक तेजी से उन्नत सड़कों का जाल बिछाने में भारत अग्रणी है। लेकिन सुविधाजनक एवं उन्नत होती सड़कों पर मौत की काली छाया का मंडराना सड़क विकास पर एक बदनुमा दाग है। यह दाग सरकारी रिपोर्ट में ही सामने आया है, जिसके अनुसार देश में 2022 में कुल 4,61,312 सड़क हादसे हुए, जिनमें से 1,51,997 यानी 32.9 प्रतिशत हादसे एक्सप्रेसवे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर हुए। वहीं 1,06,682 यानी 23.1 प्रतिशत हादसे राज्य राजमार्गों जबकि 2,02,633 यानी 43.9 प्रतिशत हादसे अन्य सड़कों पर हुए। रिपोर्ट कहती है कि

सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या सुरक्षात्मक साधनों का इस्तेमाल न करने वालों की रही। सीट बेल्ट न पहनने की वजह से 16,715 लोगों की इन हादसों में मौत हो गई जिनमें से 8,384 लोग ड्राइवर थे जबकि बाकी 8,331 लोग वाहन में बैठे यात्री थे। इसके अलावा 50,029 दोपहिया सवार भी हेलमेट न पहनने की वजह से इन हादसों में अपनी जान गंवा बैठे। लगातार चौथे साल घातक सड़क दुर्घटना का सबसे अधिक युवा शिकार हुए। राज्यों में तमिलनाडु में 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक 64,105 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जबकि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22,595 रही। सड़क दुर्घटनाओं का लगातार बढ़ना अनेक सवाल खड़े करता है। तभी सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख टिप्पणी कर चुका है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी को मार डालने के लिए नहीं दिए जाते। हादसों से संबंधित कानूनी प्रावधान अभी इस कदर कमजोर हैं कि किसी की लापरवाही की वजह से दो-चार या ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और आरोपी को कई बार थाने से ही छोड़ दिया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं ने कहर बरपा रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 2009 में सड़क सुरक्षा पर अपनी पहली वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं की दुनिया भर में 'सबसे बड़े कातिल' के रूप में पहचान की थी। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 78.7 प्रतिशत हादसे चालकों की लापरवाही के कारण होते हैं। वैसे एक प्रमुख वजह शराब व अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाना है। विडंबना यह है कि जहां हमें पश्चिमी देशों से कुछ सीखना चाहिए वहां हम आंखें मूंद लेते हैं और पश्चिम की जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है उन्हें सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं कि हम भी आधुनिक कहला सकें। एक आकलन के मुताबिक आपराधिक घटनाओं की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। कहीं बदहाल सड़कों के कारण तो कहीं अधिक सुविधापूर्ण अत्याधुनिक चिकनी सड़कों पर तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहनों के कारण ये हादसे होते हैं। दुनिया भर में सड़क हादसों में बारह लाख लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है, जिनमें भारत में सर्वाधिक मौते होती है। ट्रैफिक व्यवस्था कुछ अंशों में महानगरों को छोड़कर कहीं पर भी पर्याप्त व प्रभावी नहीं है। पुलिस "व्यक्ति" की सुरक्षा में तैनात रहती है "जनता" की सुरक्षा में नहीं। हजारों वाहन प्रतिमास सड़कों पर नए आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, रोज किसी न किसी को निगलने वाली "रेड लाइनें" बढ़ रही हैं। दुर्घटना में मरने वालों की तो गिनती हो जाती है पर वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएँ से प्रतिदिन मौत की ओर बढ़ने वालों की गिनती असंख्य है। वाहनों में सुधार हो रहा है पर सड़कों और चालकों में कोई सुधार नहीं। सन्-2023 तक वाहनों का उत्पादन और मांग जिस अनुपात में बढ़ेगी, सड़कें उस अनुपात में नहीं। अतः यातायात-अनुशासन बहुत जरूरी है।

नया भारत निर्मित करने, औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश के लिए सरकार सभी प्रकार के गति-अवरोधक हटा रही है। लगता है सड़कों पर भी गति अवरोध हटा रही है। कोई चाहिए जो नियमों की सख्ती से पालना करवा के निर्दोषों को मौत के मुंह से बचा सके। 1988 में बने मोटर वाहन अधिनियम का व्यावहारिकता से परे होना भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। पिछले तीन दशकों में सड़क परिवहन में आए बदलाव के अनुरूप मोटर अधिनियम में व्यापक बदलाव की दरकार है। अगर सरकार नए वाहनों को लाइसेंस देना बंद नहीं कर सकती तो कम से कम राजमार्गों पर हर चालीस-पचास किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर तो खोल ही सकती है ताकि इन हादसों के शिकार लोगों को समय पर प्राथमिक उपचार मिल सके। तेजी से बढ़ता हादसों एवं लापरवाही का हिंसक एवं डरावना दौर किसी एक प्रान्त या व्यक्ति का दर्द नहीं रहा। इसने हर भारतीय दिल को जख्मी किया है। इंसानों के जीवन पर मंडरा रहे मौत के तरह-तरह की डरावने हादसों एवं दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिये प्रतीक्षा नहीं, प्रक्रिया आवश्यक है। तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते वाले लोग सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखे वाक्य 'दुर्घटना से देर भली' पढ़ते जरूर हैं, किन्तु देर उन्हें मान्य नहीं है, दुर्घटना भले ही हो जाए।

**लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)**

# Mercedes-Benz GLE facelift और C43 4Matic त्योहारी सीजन में हुई लॉन्च, जानिए कीमत और अन्य

Mercedes-Benz GLE Facelift की बात करें तो इसमें नई फ्रंट ग्रिल दोबारा डिजाइन किए गए बंपर नई एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स व नए अलॉय व्हील दिए गए हैं। एसयूवी का समग्र डिजाइन काफी हद तक अपरिवर्तित है लेकिन हल्के अपडेट इसे अधिक आधुनिक और फ्रेस लुक देते हैं। Mercedes-AMG C43 सेडान W206-जेन अवतार में भारत में वापस आ गई है।

**नई दिल्ली।** त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ भारतीय बाजार में अपने दो नए प्रोडक्ट- GLE SUV और C43 4Matic को लॉन्च कर दिया है। कंपनी इन दोनों की शुरुआती कीमत क्रमशः 96.40 लाख रुपये और 98 लाख रुपये रखी है।

आपको बता दें कि ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। GLE को तीन वेरिएंट में उपलब्ध कराया जा सकता है और इसकी डिलीवरी नवंबर में शुरू होने वाली है। आइए, दोनों के बारे में जान लेते हैं।

**Mercedes-Benz GLE Facelift**

Mercedes-Benz GLE Facelift की बात करें तो इसमें नई फ्रंट ग्रिल, दोबारा डिजाइन किए गए बंपर, नई एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स व नए अलॉय व्हील दिए गए हैं। एसयूवी का समग्र डिजाइन काफी हद तक अपरिवर्तित है, लेकिन हल्के अपडेट इसे अधिक आधुनिक और फ्रेस लुक देते हैं।

फेसलिफ्टेड जीएलई के इंटीरियर में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें एस-क्लास से लिया गया एक नया टच सेंसिटिव, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील शामिल है। इसके अलावा, इसमें नए ट्रिम और अपहोल्स्ट्री विकल्प और एक फ्रेस एमबीयूएक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

**Mercedes-AMG C43**

Mercedes-AMG C43 सेडान W206-जेन अवतार में भारत में वापस आ गई है। स्टैंडर्ड सी-क्लास सेडान से अलग करने के लिए, C 43 में वर्टिकल स्लैट्स के साथ एएमजी की पैनामेरिकाना ग्रिल, एल-आकार के एकीकृत एलईडी डीआरएल वाले एलईडी हेडलाइट्स, ब्लैक एक्सेंट के साथ फ्रंट बम्पर पर बड़े एयर इनटेक, ग्लॉस-ब्लैक ओआरवीएम, 18-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील, क्वाड एग्जॉस्ट पाइप और एक आक्रामक डिफ्यूजर दिया गया है।

इंटीरियर की बात करें तो ये सेडान 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 11.9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए AMG-Specific डिजिटल ग्राफिक्स के साथ आती है। इसके अतिरिक्त, इसमें लेदर फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, कार्बन-फाइबर एलीमेंट और लाल रंग की सीट बेल्ट जैसे अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं।

# 2024 Yamaha MT-09 की पहली झलक आई सामने, 7 नवंबर को EICMA 2023 में होगी पेश

**नई MT-09 पहले से ज्यादा आक्रामक और तेज दिखती है। इसकी हेडलैंप यूनिट काफी स्लीक है और इसमें 2 एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप स्ट्रिप्स दिए गए हैं। 2024 Yamaha MT-09 में एक मस्कुलर फ्यूल टैंक है जबकि टेल सेक्शन काफी फ्रेस और मजबूत है। फीचर्स की बात करें तो 2024 MT-09 में अब एक नया 5-इंच फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।**

**नईदिल्ली।** Yamaha Motor Company ने अपडेटेड MT-09 की पहली झलक पेश की है। इसे EICMA 2023 में पेश किया जाएगा, जो 7 नवंबर से मिलान में आयोजित होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 2024 Yamaha MT-09 को 2024 के स्प्रिंग सीजन में ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसे भारत में लॉन्च करने को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं घोषित की है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

**डिजाइन**

नई MT-09 पहले से ज्यादा आक्रामक और तेज दिखती है। इसकी हेडलैंप यूनिट काफी स्लीक है और इसमें 2 एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप स्ट्रिप्स दिए गए हैं। 2024 Yamaha MT-09 में एक मस्कुलर फ्यूल टैंक है, जबकि टेल सेक्शन काफी फ्रेस और मजबूत है। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स अब सेल्फ कैंसिलेशन फंक्शनलिटी के साथ आते हैं। इसे भारतीय बाजार में आते-आते समय लग सकता है।

**फीचर्स**

फीचर्स की बात करें, तो 2024 MT-09 में अब एक नया 5-इंच फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें अब कनेक्टिविटी फीचर्स और मोबाइल इक्युपमेंट को चार्ज करने के लिए टाइप-सी सॉकेट मिलता है। निर्माता ने इसमें यामाहा राइड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी जोड़ा है। 2024 Yamaha MT-09 को 5 राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनमें 3 प्रीसेट और 2 कस्टमाइजेबल हैं।

**स्पेसिफिकेशन**

सस्पेंशन ट्यूनिंग को दोबारा ट्यून किया गया है। अब ये आगे से थोड़ा कम कठोर है और इंजन सस्पेंशन अब अधिक कठोर है। डैम्पिंग स्पेशिफिकेशन को भी बदल दिया गया है और पीछे के सस्पेंशन को भी बदल दिया गया है। यामाहा अब ब्रिजस्टोन बैटलैक्स हाइपरस्पोर्ट S23 टायर का उपयोग कर रही है। टायरों की बात करें तो, वे नए 17-इंच स्पिनफोर्ज्ड एल्यूमीनियम व्हील के साथ आते हैं।

**इंजन**

2024 MT-09 को पावर देने वाला वही 890 cc, CP3, तीन-सिलेंडर इंजन है, जो लिक्विड-कूल्ड है। यह 10,000 आरपीएम पर 117.3 बीएचपी और 7,000 आरपीएम पर 93 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है। ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स एक 6-स्पीड यूनिट है, जो स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ आता है।

# 2024 रॉयल इनफील्ड हिमालियन की स्पेसिफिकेशन का हुआ खुलासा, पहले से इतना बदल जाएगी ये टेक-लोडेड बाइक

2024 Royal Enfield Himalayan अपने पूर्ववर्ती की तुलना में रेशियो में भी बड़ी है। बाइक की लंबाई 2245 मिमी चौड़ाई 852 मिमी और ऊंचाई 1316 मिमी है व्हीलबेस 1510 मिमी है। इसमें एक गोल एलईडी हेडलैंप के साथ गोलाकार फ्यूल टैंक दिया गया है। नई हिमालयन में अब 4 इंच की टीएफटी स्क्रीन है जिसमें स्मार्टफोन के माध्यम से नेविगेशन और म्यूजिक कनेक्टिविटी शामिल है।

**नई दिल्ली।** Royal Enfield ने बहुप्रतीक्षित मोटरसाइकिल Himalayan 452 के स्पेसिफिकेशन की घोषणा कर दी है। 2024 रॉयल एनफील्ड हिमालयन पूरी तरह से नई है और ये वर्तमान में बिक्री पर मौजूद हिमालयन 410 की जगह लेगी। इस एडवेंचर बाइक में अब एक बिल्कुल नया फ्रेम, बड़ी क्षमता वाली मोटर और बहुत सारे नए तकनीकी अपडेट शामिल हैं।

**डायमेंशन**

नई पीढ़ी की रॉयल एनफील्ड हिमालयन अपने पूर्ववर्ती की तुलना में रेशियो में भी बड़ी है। बाइक की लंबाई 2,245 मिमी, चौड़ाई 852 मिमी और ऊंचाई 1,316 मिमी है, व्हीलबेस 1,510 मिमी है। इसमें एक गोल एलईडी हेडलैंप के साथ गोलाकार फ्यूल टैंक दिया गया है। साथ ही इसे राइडर और पिलियन के लिए स्प्लिट सीट दी गई है।

नई हिमालयन अब एक स्ट्रेस्ड मेंबर के रूप में इंजन का उपयोग करते हुए रियर सबफ्रेम के साथ ट्विन-स्पार फ्रेम का उपयोग करती है। एयरबॉक्स को फ्यूल टैंक शेल के ठीक नीचे ऊपर ले जाया गया है, जिससे अधिक हवा का सेवन और बेहतर पानी निकालने की क्षमता मिलती है, जबकि फ्यूल टैंक को सीट के नीचे ले जाया गया है और इसकी क्षमता 17 लीटर है। पूरी बाइक का वजन 196 किलोग्राम है, जो पहले से 3 किलो कम है।

**इंजन**

इसे 452 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8000 आरपीएम पर 39 बीएचपी का पावर और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम का पीक टॉर्क प्रदान करता है। इस पावरट्रेन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। नई हिमालयन में 825 मिमी लंबी स्टॉक सीट भी मिलती है, जिसे 845 मिमी तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी आपको एक्सेसरी के तौर पर 805 मिमी की कम ऊंचाई वाली सीट भी बेचेगी।

**टेक**

तकनीक की बात करें, तो नई हिमालयन में अब 4 इंच की टीएफटी स्क्रीन है जिसमें स्मार्टफोन के माध्यम से नेविगेशन और म्यूजिक कनेक्टिविटी शामिल है। यूनिट को अलग-अलग डिस्प्ले मिलते हैं, जबकि लेआउट को पर्सनलाइज्ड किया जा सकता है। इसे आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए इसमें एंटी-ग्लेयर स्क्रीन भी है। बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील सेटअप के साथ 140-सेक्शन चौड़ा रियर टायर है।

# कार के लिए बहुत उपयोगी हैं ये टॉप-5 गैजेट्स, मुश्किलों में देगें आपका साथ

हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन और अफोर्डेबल गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी कार की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ उसे और उपयोगी बना देंगे। मौजूदा समय में ये सबसे उपयोगी गैजेट है जो कार के टायर प्रेशर को मॉनीटर करता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या टीपीएमएस में वाहन के प्रत्येक पहिये पर लगे छोटे वायरलेस सेंसर शामिल होते हैं।

**नई दिल्ली।** अगर आपके पास एक कार है और आप उसे अधिक सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ जरूरी चीजों की लिस्ट लेकर आए हैं। हम आपको 5 ऐसे बेहतरीन और अफोर्डेबल गैजेट्स के बारे में बताएंगे, जो आपकी कार की शोभा बढ़ाने के साथ-साथ उसे और उपयोगी बना देंगे। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

**TPMS**

मौजूदा समय में ये सबसे उपयोगी गैजेट है, जो कार के टायर प्रेशर को मॉनीटर करता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या टीपीएमएस में वाहन के प्रत्येक पहिये पर लगे छोटे वायरलेस सेंसर शामिल होते हैं। सेंसर हेड-अप डिस्प्ले के माध्यम से प्रत्येक वाहन के टायर के वास्तविक समय के वायु दबाव को प्रदर्शित करते हैं। इसकी मदद से आप हमेशा टायरों पर नजर रख सकते हैं।

**Dash Cam**

रोड रेज की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अपनी कार में डैश कैम लगाना जरूरी हो गया है। इसके अलावा, कैमरे का उपयोग सड़क यात्रा पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। इसको अलावा Dash Cam की मदद से रिकॉर्डिंग का उपयोग करके बीमा कंपनियों को भी दुर्घटना के बारे में बताया जा सकता है।

**Jumper cable**

कई बार बैटरी में दिक्कत होने की वजह से, कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। ऐसे में Jumper cable आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। इन केबलों का उपयोग कार स्टार्ट करने के लिए दूसरे वाहन की बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पावर लेने के लिए किया जा सकता है।

**Portable Tyre Inflator**

आपकी कार का टायर किसी भी समय पंचर हो सकता है, ऐसे में पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर कार के फ्लैट टायर में हवा भरने के लिए वाहन के 12V पावर आउटलेट से जोड़ा जा सकता है। फिर आप गाड़ी चलाकर निकटतम पंचर की दुकान पर जा सकते हैं।

**Reverse Parking Camera**

कार को पार्क करते समय ये गैजेट काफी उपयोगी साबित होता है। अगर आपकी कार में स्टैंडर्ड रूप से Reverse Parking Camera नहीं दिया गया है, तो आप इसे ऑफ्टर मार्केट खरीद सकते हैं और अपने ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बढ़ा सकते हैं।

# कल्पना, प्रयास और सफलता

पीके खुराना

**इस सारे विवेचन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वह यह है कि आप जिस प्रकार रोजमर्रा की समस्याओं से जूझने के लिए अपनी तर्क और विश्लेषण शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अपनी कल्पनाशक्ति का प्रयोग करना भी आरंभ करें। यह आदत सायास अपनाएं। कल्पनाशक्ति का योजनाबद्ध प्रयोग आरंभ कर दिया तो आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे '**

कहा जाता है कि ज्ञान शक्ति है, पर क्या आप जानते हैं कि यह एक अधूरा सच है। ज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं है। ज्ञान, शक्ति में तभी परिवर्तित होता है जब इसे प्रयोग में लाया जाए। यही नहीं, जब इसे रचनात्मक ढंग से काम में लाया जाए तो यह एक बड़ी शक्ति बन जाता है। ज्ञान के रचनात्मक प्रयोग में कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक आरंभ से ही कल्पना शक्ति को मानव समाज का सर्वोत्तम उपहार मानते रहे हैं। रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास उसी तरह संभव है जैसे हम तैरना, पढना या चित्र बनाना सीखते हैं। वस्तुतः लगभग हर कला को वैज्ञानिक विधि से सीखा जा सकता है। कला और विज्ञान के इस संगम ने ही मानव को अपरिमित ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारी कल्पना शक्ति उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी स्मरण शक्ति। कल्पना शक्ति के विकास के लिए बुद्धिमत्ता, ज्ञान अथवा अनुभव की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि प्रयास, प्रेरक स्थितियों अथवा हमारी आवश्यकता की होती है। जान पर आ बनी हो तो हमारी कल्पना शक्ति ज्यादा मुखर हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक ने इसे एक बार सिद्ध कर दिखाया। अमेरिका की एक विश्वप्रसिद्ध कंपनी के विशाल भवन की बारहवीं मंजिल पर स्थित एक कमरे में बैठे कर्मचारियों व अधिकारियों से उन्होंने एक प्रश्न किया, 'यदि अभी भूकंप आ जाए और यह विशाल भवन दो मिनट में गिरने वाला हो तो आप क्या करेंगे?' अधिकांश लोग कोई सार्थक हल सुझा पाने में असमर्थ रहे।

इसके बाद वे साथ के कमरे में गए और लोगों से इधर-उधर की बातें करने लगे। इतने में उनका एक सहायक बदहवास हालत में वहां भागता आया और बोला कि भूकंप आ गया है, सारा भवन गिर रहा है। उनके सहायक का अभिनय इतना शानदार था कि कमरे में मौजूद लोगों को सहज ही उसकी बात पर विश्वास हो गया। दो मिनट के भीतर कमरे में मौजूद सभी लोग भवन से बाहर थे। कोई पाइप से लटका या खिडक़ी से कूदा, पर सभी भवन से बाहर आ गए! जीवन को खतरे में जानकर कल्पनाशक्ति मुखर हुई और जवान, बूढ़ा, औरत, मर्द, लड़कियां, स्वस्थ व शरीर से कमजोर, हर तरह का व्यक्ति, जान बचाने की जुगत में जुट गया और सफल भी हुआ। इस प्रयोग से कई बातें एक साथ सिद्ध हो गईं। पहली तो यह कि मुखर कल्पनाशक्ति कई तरह के चमत्कार कर पाने में समर्थ है। दूसरे, हर व्यक्ति कल्पनाशील हो सकता है। तीसरे, कल्पनाशक्ति की मुखरता के लिए प्रयास की सघनता (इंटेसिटी ऑफ एफर्ट) तथा संचालक शक्ति (ड्राइविंग पावर) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कल्पनाशक्ति के प्रयोग में उम्र कोई बाधा नहीं है। बाद में अलग-अलग प्रयोगों से यह भी सिद्ध हो गया कि उम्र के साथ कल्पनाशक्ति का क्षरण नहीं होता, बल्कि कल्पनाशक्ति का प्रयोग करते रहने वाले व्यक्ति की कल्पना बढ़ती उम्र के साथ अधिक मुखर और परिपक्व हो जाती है। वस्तुतः बड़ी उम्र के लोगों में रचनात्मक कल्पनाशक्ति के अभाव के जो कारण पाए गए, वे परंपरागत विश्वास के एकदम विपरीत निकले। हमारी शिक्षा पद्धति में केवल स्मरणशक्ति के प्रयोग पर अनावश्यक बल, और जीवन के मशीनी अंदाज ने कल्पनाशक्ति के विकास पर कुठाराघात किया है। विभिन्न परीक्षाओं एवं प्रतियोगिताओं में कल्पनाशक्ति के बजाय ज्ञान और स्मरणशक्ति का महत्व बढ़ जाने के कारण कल्पनाशक्ति के विकास का कोई प्रयास आरंभ ही नहीं हुआ। जहां कल्पनाशक्ति घटी वहां प्रयास पहले समाप्त हुआ, कल्पनाशक्ति का क्षरण बाद में आरंभ हुआ।

हमारा चेतन मस्तिष्क दो भागों में बंटा हुआ है। इसका पहला भाग तर्कशील है जो विश्लेषण और तुलना के बाद दो या अधिक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करता है, और दूसरा भाग रचनात्मक है जो मानसिक चित्र गढ़ता है, अनुमान लगाता है और नए विचारों का सृजन करता है। तर्कशील मस्तिष्क और रचनात्मक मस्तिष्क कई मामलों में एक-सा कार्य करते हैं। दोनों ही विश्लेषण और संश्लेषण (जोडऩा, मिलाना) का कार्य करते हैं। तर्कशील मस्तिष्क तथ्यों का क्रमवार विभाजन करता है, उन्हें परखता है, तुलना करता है, और तब उन्हें सिलसिलेवार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। रचनात्मक मस्तिष्क भी यही सब करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका अंतिम कार्य निर्णय देना नहीं बल्कि किसी नए विचार को जन्म देने का है। वह फैसला नहीं करता, बल्कि कुछ नए विचार सुझाता है। तर्कशील मस्तिष्क और रचनात्मक मस्तिष्क में एक और बड़ा अंतर यह है कि तर्कशील मस्तिष्क सिर्फ उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करता है जबकि रचनात्मक मस्तिष्क कल्पनाशक्ति के सहारे अज्ञात में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तथा दो और दो चार के गणितीय कार्य से भी आगे जाकर कुछ नया कर दिखाता है।

यह समझना आवश्यक है कि कल्पनाशक्ति और तर्कशक्ति एक-दूसरे के पूरक भी हैं और शत्रु भी, अतः यदि इनमें सही संतुलन न रखा जाए तो दोनों का ही नुकसान होता है। तर्कशील मस्तिष्क का कार्य मुख्यतः ऋणात्मक है। 'अरे, इसमें तो यह दोष है', 'नहीं, नहीं, यह नहीं चलेगा', 'ऐसा भी कहीं होता है' आदि-आदि तर्कशील मस्तिष्क की उपज हैं, जबकि रचनात्मक मस्तिष्क को मुख्यतः धनात्मक या विधायी कार्य करने होते हैं, तभी वह नए विचारों का सृजन कर पाता है। रचनात्मक मस्तिष्क बुरी से बुरी स्थिति में भी आशा की किरणें खोजता है जबकि तर्कशील मस्तिष्क हर योजना में कमियां ढूंढता है। कल्पनाशक्ति की उड़ान से उपजे कई विचार तो प्रथम दृष्टि में ही असंभव लगते हैं, लेकिन बाद में उनमें से कइयों को वास्तविकता में बदलना संभव हो जाता है। यह देखना आवश्यक है कि हमारा तर्कशील मस्तिष्क हमारे रचनात्मक मस्तिष्क में उपजने वाले विचारों की भ्रूण हत्या न कर दे, क्योंकि लगभग हर नए विचार को तुरंत तर्कसंगत ढंग से गलत सिद्ध किया जा सकता है। कई बार तो ये तर्क इतने पुख्ता लगते हैं कि व्यक्ति अपनी योजना को सिरे से ही त्याग देता है, अतः यह आवश्यक है कि विचारों को तुरंत ठीक और गलत या संभव और असंभव की कसौटी पर परखना आरंभ कर देने से पहले उसे कुछ और परिपक्व हो लेने देना चाहिए। स्मरणशक्ति एक मशीनी अंदाज का काम है। एक विषय को बार-बार दोहराते रहने से वह हमें याद हो जाता है, या एक कार्य को बार-बार दोहराने से हमें उसका अभ्यास हो जाता है। उसमें सृजनात्मक कुछ भी नहीं है। कल्पनाशक्ति किसी विषय को दोहराते समय भी उसे दोहराने या याद करने के बेहतर और आसान तरीके खोज निकालती है। कल्पनाशक्ति का प्रयोग एक रचनात्मक क्रिया है और कल्पनाशक्ति एक रचनात्मक, सृजनात्मक शक्ति है। किसी भी समस्या से दो-चार होने पर अपने आसपास नजर दौड़ाइए। यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि कितने लोगों को वैसी या उस जैसी समस्या से जूझना पड़ा, उन्होंने समस्या का समाधान कैसे किया, उन्हें क्या कठिनाइयां आईं, आदि-आदि। समस्या के बारे में खुद सोचिए, मित्रों और शुभचिंतकों से विचार-विमर्श कीजिए। एक-दो बार के प्रयत्न से ही आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इस सारे विवेचन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वह यह है कि आप जिस प्रकार रोजमर्रा की समस्याओं से जूझने के लिए अपनी तर्क और विश्लेषण शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अपनी

## संपादक की कलम से

### फोन में सेंधमारी

बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल ने विपक्ष के कुछ नेताओं को अलर्ट भेजा कि आपके आईफोन हैक किए जा सकते हैं। हमलावर आपके फोन के संवेदनशील डाटा, कैमरे और माइक्रोफोन आदि तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। एप्पल ने यह अलर्ट सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही नहीं भेजा, बल्कि ऐसे लोगों तक भी भेजा है, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं हैं। कुछ पत्रकारों और स्कॉलर्स तक भी यह अलर्ट पहुंचा है। यह अलर्ट 150 देशों में भी भेजा गया है, जहां एप्पल के आईफोन इस्तेमाल किए जाते हैं। साफ मायने हैं कि यह चेतावनी वैश्विक है, लिहाजा विपक्षी नेताओं की चीखा-चिल्ली महज सियासत है। एप्पल ने अपने बयान में यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि खुफिया संकेतों के आधार पर ऐसे अलर्ट आते हैं, जो अधूरे और गलत भी साबित हो सकते हैं। कंपनी ने सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावरों की बात तो की है, लेकिन किसी 'विशेष सरकार' का खुलासा नहीं किया है। एप्पल ने हैकिंग के ऐसे खतरों से निपटने वाले सिस्टम से इंकार किया है। कंपनी यह भी नहीं बता सकती कि अलर्ट किन हालात में देना पड़ा, क्योंकि यह जानकारी देने से हैकर्स उससे बचने के रास्ते खोज सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि फोन हैकर्स चीन, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के भी हो सकते हैं! एप्पल ने एक ही समय, एक ही साथ, विपक्षी नेताओं और 150 देशों को यह चेतावनी-संदेश भेजा है, लिहाजा संदेहास्पद और सवालिया लगता है। यदि हैकिंग हुई है या की जा रही है, तो वह अलग-अलग स्थान पर, अलग-अलग समय में की जानी चाहिए। फिर भी मान सकते हैं कि मोदी सरकार ने विपक्ष के कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं के फोन हैक कराए हैं, लेकिन 150 देशों और अराजनीतिक चेहरों के फोन हैक कराने में सरकार के सरोकार क्या हो सकते हैं?

उनसे हासिल क्या होगा? भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया भर में करीब 146 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। क्या ये सभी मोदी सरकार के निशाने पर हैं अथवा सभी को अलर्ट भेजा गया था? एप्पल को इस संदर्भ में तमाम स्पष्टीकरण देने चाहिए। बहरहाल केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणानुसार जांच शुरू कर दी गई है। एप्पल भी जांच के दायरे में होगी। एप्पल से कथित 'राज्य-प्रायोजित हमलों' पर वास्तविक और सटीक जानकारी मांगी गई है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन) इसकी जांच कर तह तक जाने की कोशिश करेगी। मंत्री ने इसे भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश और भटकाने वाली विपक्ष की राजनीति करार दिया है। 'फोन में सेंधमारी' कोई नया मुद्दा नहीं है। किसी की निजता और गोपनीयता पर हमला भी नहीं है। इजरायल से खरीदे गए जासूसी सॉफ्टवेयर की चर्चा एक बार फिर मुखर हो रही है। हालांकि सर्वोच्च अदालत की निगरानी में जो जांच कराई गई थी, उसमें कुछ भी ठोस सामने नहीं आया था। तब शीर्ष अदालत ने अपने-अपने फोन सरकार में जमा कराने का विकल्प भी दिया था, ताकि भीतरी जांच हो सके कि उसकी जासूसी कराई गई अथवा नहीं। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपना फोन जमा नहीं कराया था। आज फिर पुराने, अपरिपक्व बयान दोहराए जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि फोन हैकिंग के संदर्भ में अडाणी की भूमिका क्या हो सकती है? राहुल गांधी ने किसे 'तोता' कहा है? क्या कांग्रेस सरकारों के कार्यकालों में अडाणी व्यापार नहीं करते थे? क्या उन्हें ठेके नहीं दिए गए? देश को ऐसे सवाल कांग्रेस नेता से पूछने चाहिए। दरअसल जिनके फोन में सेंधमारी के आरोप उछले हैं, उनमें अधिकतर चेहरे राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हैं अथवा आरोपित हैं। मोदी सरकार को उनके फोन हैक कर हासिल क्या होगा? वे भाजपा को राजनीतिक चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं हैं। यदि एप्पल के चेतावनी-संदेश में कुछ ठोस था, तो विपक्ष को प्रेस ब्रीफिंग के बजाय प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। बहरहाल, उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी व कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह मामला उठाया है।

## राय

### जदरांगल में सीयू मुजरिम

अब मसला केंद्रीय विश्वविद्यालय को खंडित करने का नहीं रहा, बल्कि इसके जदरांगल परिसर को खुर्द-बुर्द करने का है और यह हो चुका है। जिन्हें विश्वास था कि जदरांगल परिसर की सियासत में केवल भाजपा दोषी रही, उन्हें आंखें खोलकर देख लेना चाहिए कि कांग्रेस सरकार भी इसे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को वरदान बनाने पर उतारू है। अंततः केवल शांता कुमार ने ही जुबान खोली है, जबकि कांगड़ा से तमाम कांग्रेसी विधायक तो मीठी गोलियां चाट रहे हैं। आश्चर्य यह कि कांगड़ा के कोटे में एकमात्र मंत्री चौधरी चंद्र कुमार भी मुंह में दही जमा के बैठे हैं, जबकि कभी उनकी व सुधीर शर्मा की बदौलत धर्मशाला परिसर का प्रस्ताव बचा था। संस्थान बर्बाद कैसे हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्रीय विश्वविद्यालय के खंडित अध्याय है। इस नासूर में पहले धूमल और फिर जयराम सरकारें रहीं और अब सुक्खू सरकार के लिए भी यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं, वरना कब के तीस करोड़ जमा करवाकर काम शुरू हो चुका होता। भले ही सारा विश्वविद्यालय देहरा में बसा दिया जाए, इससे ऐसे संस्थान के महत्त्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंदी सियासत की परछाइयों में रह कर उच्च शिक्षा की कई मंजिलें ध्वस्त हो चुकी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तमाम वे नेता जो धर्मशाला परिसर से खेलते रहे, वे जीत का एहसास कर सकते हैं और जो हारे, वे पीठ पर राजनीतिक चाबुक का प्रहार देख सकते हैं। आश्चर्य यह कि जिस क्रिकेट की हवाएं अनुराग ठाकुर को धर्मशाला में रोशनी दिखाती हैं, वह सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय को बटोरता रहा।

कुछ इसी तरह का इतिहास कांगड़ा के सांसद किशन कपूर का भी रहा, जिन्होंने बतौर विधायक सर्वप्रथम धर्मशाला में सीयू के खिलाफ अपना रवैया रचा था। हिमाचल में एम्स, आईआईएम, मेडिकल कालेज और खास तौर पर हमीरपुर के मेडिकल कालेज की इमारतें बिना किसी हुज्जत के चोटियां गिनती रहीं, लेकिन परीक्षाएं धर्मशाला में सीयू की रहीं। धूमल सरकार ने पहले इसकी प्रस्तावित जगह की मिट्टी पलीद की, फिर जदरांगल की संभावना में उनके सिपहसालार रविंद्र रवि ने अपने बयानों से इस स्थान को अपमानित किया। हैरानी यह कि जदरांगल की जमीन को मुजरिम बनाते हुए कभी केंद्रीय वन मंत्रालय के डंडे बरसाए और कभी कोलकाता के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के जबड़ों में इसे फंसाया। किसी तरह स्वीकृतियां मिलीं, तो अब सुक्खू सरकार ने जमीन की पैमाइश घटाकर भी तीस करोड़ के भुगतान पर ताले लगा रखे हैं। एक ओर जदरांगल परिसर के प्रति सरकार की उपेक्षा से आहत पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार आहत हैं और दूसरी ओर देहरा परिसर के निर्माण में चारों घंटे काम की रफ्तार में हर फाइल क्लीयर है। इस सबके बीच केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जो इतिहास इकट्ठा किया है, उसमें हिमाचल की प्रतिष्ठा को ही दाग लग रहे हैं।

नियुक्तियों से लेकर अध्ययन की परिपाटी तक यह संस्थान एक खास स्वीकृतियों का सृजन कर चुका है, जहां विचारों की पृष्ठभूमि में एकांगी सोच का दायरा बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के सामने हिमाचल की अर्थव्यवस्था, ट्राइबल लाइफ तथा प्राकृतिक आपदाओं पर अध्ययन व शोध के बजाय प्राथमिक विषय यह है कि जम्मू-कश्मीर की हवाओं का रुख किधर है। अभी यह घोषणा हो चुकी है कि धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय यह पता लगाएगा कि धारा 370 हटने व जम्मू-कश्मीर के बंटने के बाद वहां क्या अंतर आ रहा है, इसके ऊपर धर्मशाला सीयू शोध करेगा। धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय की जम्मू-कश्मीर की चिंता विभिन्न संगोष्ठियों में भी झलकती है, जबकि जम्मू व कश्मीर में दो अलहदा-अलहदा केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तथा एक अन्य संस्थान की लद्दाख के लिए भी पैरवी होती रही है। बहरहाल ताले में बंद धर्मशाला परिसर के साथ होती रही अनवरत राजनीति में अब सुक्खू सरकार का नाम भी जुड़ रहा है। शिक्षा में ऐसे अभिप्राय का असर अंततः छात्र समुदाय को ही अनिश्चितता में धकेलता है।

# घोषणा संस्कृति की परंपरा

आजकल इस देश की धरा वीरों से वंचित हो गई लगती है। लेकिन आजकल कुछ नए वीरों का पैदा हो जाना एक ऐसे बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, कि जिसके कारण यह ऊर्जाहीन होती धरा सनसनीखेज खबरों से भर जाती है। गोदी मीडिया को पुचकार मिलती है। पहले वीरता के अभाव ने पूरे देश में अवसाद और बेचारगी को जन्म दे दिया था। जिसके साथ जो भी हो रहा था, वह उसे एक दीर्घ उच्छवास से स्वीकार कर लेता और इसका नया कारण कोरोना से पैदा मृत्युभय बता देता। गंभीरता से समाज टटोला तो पाया कि नया समाज बना सकने वालों की वीरता कब से दिवंगत हो गई। अब काम का अधिकार मांगने वाले राहतों, रियायतों और सस्ती साझी रसोइयों से निबटा दिए गए हैं। जरूरत महामारी से खंडित हो गए समाज को श्रम वीरता का अर्थ बड़बोलापन हो गया। जो जितनी दूर की हांक सके, उतना ही बड़ा इस देश का नवनिर्माता। यूं दया-धर्म का मूल है दोहराने वाले बहुत से वाक्यवीर पैदा हो गए। कार्य संस्कृति की जगह राहत और रियायत उद्घोषक संस्कृति ने कुछ इस प्रकार जन्म लिया, कि पेट भरने के लिए भूखे, बेकार और बीमारी से उठे लोगों की कतारें दानवीरों के मुफ्त और रियायती जलपान गृहों के बाहर लगनी शुरू हो गईं। नम्बर दो का धंधा करने वाले, महामारी के दिनों में कभी के मनोविज्ञान की बैसाखियों से चोरबाजारी करने वाले अनैतिकता के रणबांकुरे अचानक लंगर और राहतों से उपकार करते हुए अपने इहलोक के साथ परलोक की चिंता करने चल दिए। इससे छुटकारा पाने के लिए देश की सरकार की ओर किसी नई कार्य संस्कृति की रूपरेखा के लिए देखा जा सकता है।

महामारी का दबाव हटने के साथ इस नये सामान्य होते माहौल में उससे यह उम्मीद रखना बेजा भी नहीं था, लेकिन कार्य संस्कृति के साथ उद्यम और मेहनत की परेशानी जुड़ी होती है। इसके नतीजे भी हथेली पर सरसों जमने की तरह तत्काल नहीं आते। इसलिए ऐसा कंटकपूर्ण राह अपनाने के स्थान पर अब सरकारी दरीचों से घोषणावीरों की जमात पैदा हो गयी। अब सत्ता के मीनारों पर तो हर कोई कब्जा करना चाहता है। जो वहां जम कर बैठे हैं, वे सत्ता पक्ष हैं, जिसका लक्ष्य है जब तक जीवन, तब तक भोगो। और जब जीवन क्षीण हो, झुठलाने लगे तो अपनी कुर्सियों के सर्वाधिकार नाती-पोतों के नाम सुरक्षित करवा जाओ। लेकिन बाहर सडक़ पर ट्रैफिक जाम लगा मोर्चाबंद होता विपक्ष भी तो है। वह सत्ता पर पुश्तैनी अधिकार मानने वाले इन महामानवों के नीचे से कुर्सी खींचने की फिराक में लगा रहता है। आजकल मुकाबला, संघर्ष की वीरता, महंगाई नियंत्रण, भ्रष्टाचार उन्मूलन या बेकार कांपते हाथों को काम देने में नहीं दिखाई जाती, बल्कि घोषणा संस्कृति का अभिषेक करते हुए और भी शेखचिल्ली होने में दिखाई जाती है। चुनाव करीब हो, और लोगों के मत लुभाने की चाहत हो तो यह बातों से आसमान में पैबन्द लगाने की चाह और भी बढ़ जाती है। कोई नहीं कहता कि बेकार हाथों के लिए अब काम की गारंटी होगी। बस यही कहा जाता है कि किसी को अब भूखा न मरने देंगे। इसी की दिलासा मिलती है। महामारी से डरे हुए नौनिहालों के लिए नये शांति निकेतनों की स्थापना पर कोई बल नहीं देता। बस लोगों को बिना स्मार्ट फोनों के डिजीटल हो जाने का सन्देश दिया जाता है। हम शिक्षा को मरने नहीं देंगे, के दावे किये जाते हैं, और प्रश्न उत्तर के आब्जैक्टिव सिस्टम की ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं कि जिसमें परिणाम सौ में से सौ प्राप्त करने वाले छात्रों का नया समूह पैदा करके निकलता है। दावा करने वाले घोषणावीरों की जमात फिर प्रभावी हो गई। पर्दे के पीछे छिपे कालाबाजारियों ने अपने धंधे के नाक-नक्श संवारने शुरू कर दिए और दानवीरों ने आपके खाते में हजार, दो हजार मासिक जमा करवाने का आश्वासन भी दे दिया। लीजिए, यह वीरता की परम्परा हो गई।

**सुरेश सेठ**

## गहन विचार

# नशे की गिरफ्त में शिक्षण संस्थान व विद्यार्थी

**आवश्यकता है कि पुलिस अपनी रणनीति और कार्यशैली में बदलाव लाकर नशे के कारोबारियों पर प्रहार करे, वहीं खुफिया विभाग सटीक जानकारी जुटा कर दे। हिमाचल सरकार को चाहिए कि बढ़ती आबादी की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा जरूरतों के दृष्टिगत पुलिस थानों में पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए, उन्हें उन्नत किस्म के हथियार, स्निफर डॉग्स, उपकरण एवं वाहन उपलब्ध करवाए जाएं**

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में नशे की ओवरडोज से मृत्यु की आगोश में समाए विद्यार्थी की मौत ने हिमाचल के शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों में नशीले एवं मादक पदार्थों की आपूर्ति और नशे की गिरफ्त में आए विद्यार्थियों की ओर समस्त देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया है। सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर कोई मां-बाप किसके भरोसे राष्ट्रीय स्तर के ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को पढऩे के लिए भेज पाएंगे। छात्र अनुशासन को लेकर संस्थान की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि स्टडी टाइम में भी छात्र सरेआम बाहर घूमते रहते थे। हालांकि पुलिस छानबीन में यह भी खुलासा हुआ है कि मृतक छात्र पर शिमला में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था। हालांकि अब संस्थान प्रबंधन ने 2 होस्टलों के वार्डन व सब वार्डन को बदल दिया है। इसके साथ ही सिक्योरिटी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और विद्यार्थियों के बाहर आने-जाने में सख्ती बरती जा रही है। अभी हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने संस्थान के भीतर व बाहर नशा बिकने की आशंका जताई थी।

इस संबंध में बाकायदा रिपोर्ट भी बनाकर सरकार को भेजी गई थी तथा पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई थी। इसके बावजूद पुलिस फिल्मों की तर्ज पर हादसा होने के बाद ही सक्रिय हुई। पुलिस की इस तफ्तीश से आसपास के इलाकों और संस्थान के साथ लगते ग्राम देई का नौण के वार्ड पन्याला के लोगों में रोष है कि यही कार्रवाई पुलिस ने पहले क्यों नहीं की, जब वे शिकायत करते थे कि उनके क्षेत्रों में भी संस्थान के छात्र नशा करते देखे गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस की यह गतिविधियां सीमित समय के लिए ही है। हमीरपुर में नशे का कारोबार चरम पर है, इसकी पुष्टि एक जनवरी 2023 से लेकर 25 अक्तूबर 2023 तक जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर और गुप्त सूचना के आधार पर एनडीपीएस के कुल 73 मामले दर्ज किए गए हैं, से भी होती है। यद्यपि पुलिस आए दिन नशा माफिया को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही है लेकिन चोरी-छिपे चिट्टा और चरस का कारोबार पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से जारी है। हिमाचल में बढ़ते नशे एवं मादक पदार्थों की चपेट में आकर अपना बहुमूल्य जीवन और भविष्य को खराब करती युवा पीढ़ी को लेकर राज्य के दो प्रमुख नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि समय रहते समाज और सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। प्रो. धूमल ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी तरफ एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी का कहना है कि व्यवस्था को बदला जा रहा है तथा संस्थान का माहौल बिगडऩे नहीं दिया जाएगा। उनका कहना है कि शीघ्र ही

संस्थान में अध्यात्म को लेकर भी कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए संस्थान प्रबंधन आर्ट ऑफ लिविंग से संपर्क करने जा रहा है ताकि विद्यार्थियों में तनाव और चिंताओं को दूर कर जीवन में खुशी और आनंद लाने की कला सिखाई जा सके। जहां तक प्रदेश में मादक पदार्थों की धरपकड़ का सवाल है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 की अवधि में आठ किलोग्राम चिट्टा पकड़ा है। बीते छह महीनों में ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 हजार 230 मामले दर्ज किए गए और इन मामलों में 1 हजार 670 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।

गिरफ्तार हुए आरोपियों में एक नाइजीरियन मूल का आरोपी भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश पुलिस अब तक 1 हजार 611 पुरुष और 58 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। साल 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 हजार 439 केस दर्ज किए गए थे। साल 2020 में 1 हजार 538, साल 2021 में 1 हजार 537 और साल 2022 में नशे के 1 हजार 516 मामले दर्ज किए गए थे। हिमाचल प्रदेश में बीते छह महीनों में 50 करोड़ का चिट्टा बरामद किया जा चुका है। यदि हिमाचल प्रदेश पुलिस की उपर्युक्त उपलब्धियों को देखा जाए तो लगता है कि नशे को लेकर हालात इतने बेकाबू भी नहीं दिखते हैं लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आज हिमाचल का कोई भी गांव-कस्बा ऐसा नहीं बचा है जहां चिट्टे और चोरियों ने अपनी दस्तक न दी हो। चोरियों के मामले में चोरों को पकडऩे में तो पुलिस लाचार ही नजर आती है। ड्रग्स और मादक पदार्थों के खतरे को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) लाया गया था। यह कानून किसी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ के उत्पादन, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण या उपभोग करने से रोकता है, जबकि नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 2020 में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से शुरू किया गया था।

हालांकि हिमाचल में प्रतिदिन पुलिस द्वारा चिट्टे और चरस के आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, फिर भी बहुतायत में नशीले एवं मादक पदार्थों की बिक्री का धंधा अभी भी जोरों से जारी है। आवश्यकता है कि पुलिस अपनी रणनीति और कार्यशैली में बदलाव लाकर नशे के कारोबारियों पर प्रहार करे, वहीं खुफिया विभाग सटीक जानकारी जुटा कर दे। हिमाचल सरकार को चाहिए कि बढ़ती आबादी की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा जरूरतों के दृष्टिगत पुलिस थानों में पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए, उन्हें उन्नत किस्म के हथियार एवं उच्च प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स, उपकरण एवं वाहन इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएं। निःसंदेह विद्यार्थियों को भी स्वयंमेव जागरूक होना पड़ेगा और अपनी शिक्षा पर ध्यान देने के साथ-साथ देवभूमि हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप आदर्श-आचरण प्रस्तुत करना होगा। तभी नशे से मुक्ति मिलेगी।

# सिक्योर और अनसिक्योर लोन में क्या है अंतर ? जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट

बैंक और वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से दो प्रकार के लोन प्रदान करते हैं। पहला सिक्योर लोन और दूसरा अनसिक्योर लोन। आज जानिए क्या है दोनों लोन की परिभाषा और दोनों लोन में कितना है अंतर। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे की आपके लिए दोनों लोन में कौन सा अच्छा ऑप्शन है।

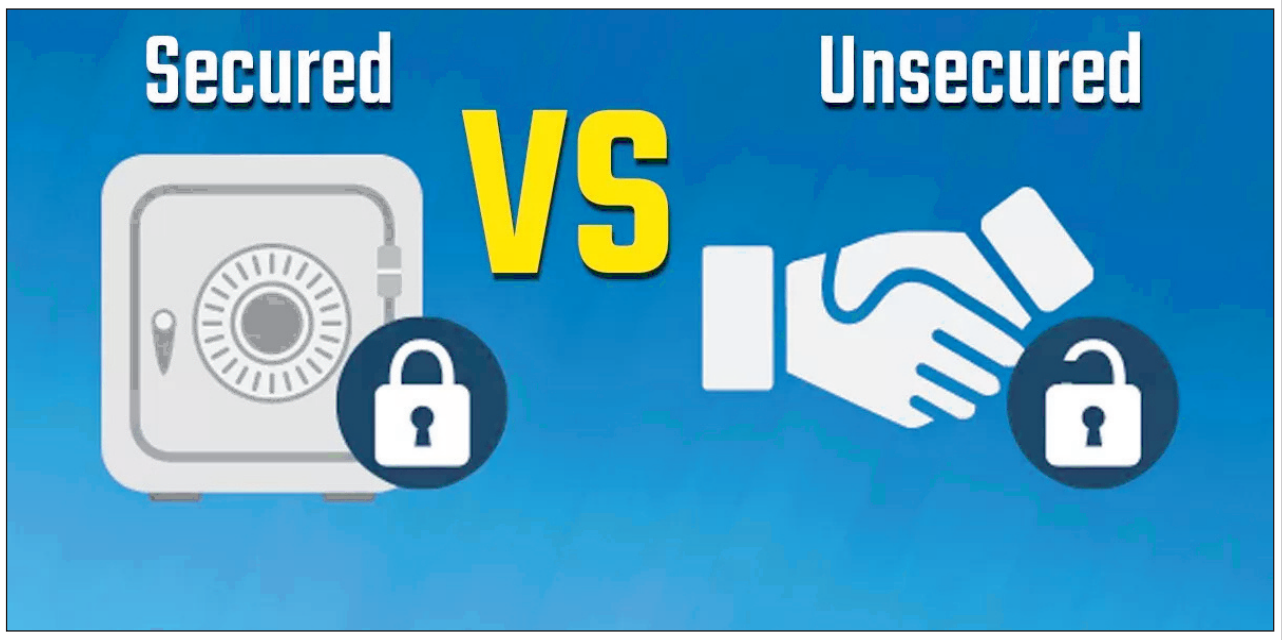


**नई दिल्ली।** हम अकसर अपने जीवन में अलग-अलग काम के लिए लोन लेते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से दो प्रकार के लोन देते हैं। पहला सिक्योर लोन और दूसरा अनसिक्योर लोन है। चलिए जानते हैं इन दोनों लोन में क्या है अंतर और आपके लिए कौन सा है बेस्ट।

**क्या होता है सिक्योर लोन ?**

आसान भाषा में कहें तो सिक्योर लोन एक ऐसा लोन होता है जिसे लेना के लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप सोना गिरवी रख कर ब्याज पर पैसा उठाते हैं, इसे ही सिक्योर लोन कहा जाता है। यानी आपने अपने परिसंपत्ति (Asset) के ऐवज में लोन लिया है।

इसे सिक्योर इसलिए कहा जाता है कि वित्तीय संस्थान के पास आपका सोना सुरक्षा के रूप में पड़ा है अगर आपने लोन की रिपेमेंट नहीं की तो वह आपका सोना बेच कर पैसा निकाल सकता है। सोने के आलावा आपका घर, आपकी कार भी कौलेटरल के रूप में जमा हो सकते हैं।

**क्या होता है अनसिक्योर लोन ?**

सिक्योर लोन के विपरित अनसिक्योर लोन होता है। इस लोन में बैंक या वित्तीय संस्थान आपको पैसे देने के लिए किसी भी प्रकार का कैलेटरल नहीं मांगता। यानी आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती।

ऐसे लोन में देनदार के पास रिक्स ज्यादा होता है इसलिए सामान्य तौर पर अनसिक्योर लोन का ब्याज अधिक होता है। हालांकि आपको अनसिक्योर लोन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर ही दी जाती है। अनसिक्योर लोन जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन इत्यादि।

**आपके लिए कौन सा सही ?**

सिक्योर लोन आसानी से और जल्द मिल जाते हैं। आमतौर पर देनदार सिक्योर लोन देने में नहीं हिचकिचाते क्योंकि उनके पास आपका कुछ सामान गिरवी होता है। सिक्योर लोन में आपको रिपेमेंट का अधिक टाइम मिलता है और ब्याज दर भी कम होती है। इसके अलावा आपको अधिक लोन मिलने की भी संभावना होती है।

वहीं अनसिक्योर लोन भी आपकी जल्द मिल जाता है लेकिन उसपर ज्यादा ब्याज दर लगता है। साथ ही लोन पुनर्भुगतान करने की सीमा भी कम होती है। दोनों लोन की विशेषताएं देखें तो लोगों को ज्यादा सिक्योर लोन पसंद आती है ऐसे में आपके लिए बेस्ट लोन का ऑप्शन क्या रहेगा यह आपके लोन लेने की जरूरत पर निर्भर करता है। हालांकि अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है तो आपके लिए अनसिक्योर लोन एक अच्छा विकल्प बन सकता है।

# अब रूस में आसानी से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं भारतीय, जानिए क्या है प्रोसेस

भारतीय नागरिक अब रूस में अपना बैंक खाता आसानी से खोल सकते हैं। रूसी सरकार ने रूस में बैंक खाता खोलने के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए नियमों में ढील दी है। रूसी दूतावास ने कहा कि इस सुविधा से पर्यटक और शिक्षा के लिए रूस आए भारतीय छात्रों को काफी मदद मिलेगी। पढ़िए कैसे खुलवा सकते हैं अकाउंट।

**नई दिल्ली।** भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब भारतीय नागरिक रूस में अपना बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। रूसी सरकार ने अपने देश में बैंक खाते खोलने के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए नियमों को आसान बनाया है।

दरअसल एक्स (X) पर रूसी दूतावास ने इस विषय पर एक अपडेट देते हुए बताया कि अब भारतीय नागरिक रूस के बैंकों में अपना अकाउंट भारत में रहकर खुलवा सकते हैं।

**क्या है अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया ?**

रूस दूतावास ने बताया कि वैसे भारतीय जो अकाउंट खलवाने के लिए इच्छुक भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवाने के गाइडेंस के लिए ऐसे भारतीय बैंक से संपर्क करें जिसका रूसी सेंट्रल बैंक के साथ साझेदारी है।

इसके अलावा रूसी दूतावास ने कहा कि रूस पहुंचने पर, साझेदार रूसी बैंक में ₹जल्दी से बैंक कार्ड प्राप्त करना₹ और वित्तीय लेनदेन शुरू करना संभव होगा। यह सुविधा भारतीय पर्यटकों और छात्रों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक होगी।

**बड़ी संख्या में पढ़ाई करने रूस जाते हैं भारतीय छात्र**

आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रूस जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध से एक साल पहले, साल 2021 में कुल 15,814 भारतीयों ने रूसी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया था।

# शुरुआती कारोबार में रुपया हुआ मजबूत, इतने पैसे चढ़कर कर रहा ट्रेड

डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर ट्रेड कर रहा है। कल यानी बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 .28 पर बंद हुआ था। इंट्रा-डे कारोबार में कल रुपया अपने रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच गया था। जानिए शुरुआती कारोबार में कितना मजबूत हुआ रुपया और क्या है डॉलर इंडेक्स का हाल।

**दिल्ली।** गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ खुला। आपको बता दें कि कल रुपया रिकॉर्ड लो स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर के मुताकाबले भारतीय करेंसी रुपया आज शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की बढ़त के साथ 83.19 पर पहुंच गया।

**मुद्रा बाजार में रुपया**

आज इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में रुपया, डॉलर के मुकाबले 83.23 पर खुला और फिर 83.19 के शुरुआती उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 9 पैसे की बढ़त है। कल यानी बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.28 पर बंद हुआ। कल रुपया इंट्रा-डे के दौरान डॉलर के मुकाबले 83.35 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई को ट्रेजरी के प्रमुख और फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के कार्यकारी निदेशक, अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि फेड की नरमी के बाद बाजार में जोखिम की भावना प्रबल होने के कारण एशियाई मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले तेजी आई। ब्रेंट ऑयल थोड़ा बढ़कर 85.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि, आज की शुरुआत 83.22 पर अधिक है क्योंकि फेड अपनी नीति बैठक में थोड़ा नरम था

**डॉलर इंडेक्स का क्या है हाल ?**

शुरुआती कारोबार में डॉलर इंडेक्स 0.51 प्रतिशत कम होकर 106.34 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि क्रूड का वायदा 1.05 प्रतिशत चढ़कर 85.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

यूएस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 4.70 पर आ गई।

**हरे निशान पर आज बाजार**

आज शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 568.23 अंक या 0.89 प्रतिशत चढ़कर 64,159.56 पर ट्रेड कर रहा है वहीं निफ्टी 155.80 अंक या 0.82 प्रतिशत उछलकर 19,144.95 पर कारोबार कर रहा है।

# एलपीजी के बाद तेल के दाम भी हुए अपडेट, जानिए आपके शहर में क्या है एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत

कल वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी 1.31 फीसदी बढ़कर 86 .13 डॉलर प्रति बैरल हो गई जिसके बाद तेल कंपनियों ने हर दिन की तरह आज सुबह 6 बजे देश में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी है। आपको बता दें कि कल तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये से अधिक का इजाफा किया है।

**नई दिल्ली।** कल तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। ग्लोबल मार्केट में कल कच्चा तेल भी 1.31 प्रतिशत उछलकर 86.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था जिसके बाद आज सुबह 6 बजे हर दिन की तरह तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट किया है।

हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखा गया है लेकिन कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ पैसों का बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत।

**कहां बदली तेल की कीमत ?**

गुड रिटर्न के मुताबिक 2 नवंबर को तेल की कीमतें इस प्रकार हैं:

चेन्नई में पेट्रोल 102.75 रुपये और डीजल 94.34 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

नोएडा में पेट्रोल 97.00 रुपये और डीजल 90.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

गुरुग्राम में पेट्रोल 96.89 रुपये और डीजल 89.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

लखनऊ में पेट्रोल 96.47 रुपये और डीजल 89.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

**इन शहरों में स्थिर रही कीमत**

नई दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

**1 बैरल में कितना कच्चा तेल ?**

आयातीत कच्चे तेल के बैरल में करीब 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। इस क्रूड ऑयल से देश में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ बाय प्रोडक्ट जैसे अलकतरा भी निकलती है।

# NSE को सितंबर तिमाही में हुआ 13 प्रतिशत का प्रॉफिट, इतना भरा सरकार का खजाना

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर बताया कि सितंबर तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़कर 1999 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा परिचालन से कंसोलिडेट इनकम में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जानिए एनएसई ने कितना भरा सरकार का खजाना।

**नई दिल्ली।** शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने चालू वित्त वर्ष 24 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा कर दी है।

एनएसई ने सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी कर बताया कि जुलाई-सितंबर के दौरान कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 13 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 1,999 करोड़ रुपये हो गया है।

**24 प्रतिशत बढ़ा परिचालन से आय**

एनएसई ने एक बयान में कहा कि समीक्षाधीन दूसरी तिमाही में परिचालन से कंसोलिडेट इनकम 3,652 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की अवधि से 24 प्रतिशत अधिक है।

परिचालन से आय ट्रेडिंग के अलावा लिस्टिंग, इंडेक्स सेवाओं, डेटा सेवाओं और सह-स्थान सुविधा सहित अन्य राजस्व के कारण हुआ है। इसके अलावा एनएसई ने यह भी बताया कि सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट मार्जिन 50 प्रतिशत रहा।

**एनएसई ने कितना भरा सरकार का खजाना ?**

वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में, एनएसई ने सरकारी खजाने में 18,744 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जिसमें 14,858 करोड़ रुपये का एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर), स्टांप शुल्क (1,156 करोड़ रुपये), जीएसटी (975 करोड़ रुपये), आयकर (1,252 करोड़ रुपये) और सेबी (503 करोड़ रुपये) शामिल थे।

**क्या हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के आंकड़े ?**

नकदी बाजारों में एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम (एडीटीवी) साल दर साल के आधार पर 40 प्रतिशत बढ़कर 77,757 करोड़ रुपये दर्ज रहा। इक्विटी वायदा भी सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,23,019 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा इक्विटी विकल्प एडीटीवी सालाना 33 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 60,621 करोड़ रुपये रहा।

**कितना रहा स्टैंडअलोन प्रॉफिट ?**

स्टैंडअलोन आधार पर बात करें तो एनुअल बेसिस पर 2 प्रतिशत बढ़कर 1,562 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन प्रॉफिट रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,535 करोड़ रुपये था।

# त्योहार के कारण शनिवार, रविवार के अतिरिक्त इस महीने 10 दिन बैंक रहेंगे बंद, चेक करें पूरी लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कैलेंडर के मुताबिक नवंबर में बैंक 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी बैंकों की शनिवार और रविवार के नियमित छुट्टी के अतिरिक्त है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम करना है तो जल्द से जल्द निपटा लें। जानिए कब और कहां और किस कारण से बैंको में रहेगी छुट्टी।

**नई दिल्ली।** देश में इस वक्त त्योहार का माहौल है। जहां एक तरफ लोगों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल है वहीं दूसरी तरफ बैंक में जरूरी काम करवाने वाले लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कैलेंडर के मुताबिक नवंबर महीने में आज यानी 2 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार के अलावा 10 दिन और बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कुछ जरूरी काम करवाना है तो जल्द ही करवा लें क्योंकि नवंबर में इस-इस दिन बैंक बंद रहेंगे।

**त्योहार और चुनाव के कारण बैंक बंद**

आपको बता दें कि इस महीने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है जिसके कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। साथ ही 13,14 और 15 नवंबर को बैंकों में दिवाली की छुट्टी रहेगी।

**कब और कहां बैंक रहेंगे बंद ?**

तिथि यहां बैंक रहेंगे बंद कारण

2 नवंबर शिलांग नोंगक्रेम नृत्य

7 नवंबर आइजोल मिजोरम विधानसभा चुनाव, 2023

10 नवंबर शिलांग वंगाला महोत्सव

13 नवंबर अगरतला, देहरादून, गंगटोक, इंफाल, जयपुर, कानपुर, लखनऊ गोवर्धन पूजा/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/दिवाली

14 नवंबर अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, गंगटोक, मुंबई, नागपुर दिवाली (बाली प्रतिपदा)/दीपावली/विक्रम संवंत नववर्ष दिवस/लक्ष्मी पूजा

15 नवंबर गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, शिमला भाईदूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दीपावली)/निंगोल चक्कौबा/भ्रातृद्वितीया

17 नवंबर भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023

20 नवंबर पटना, रांची छठ (सुबह का अर्घ्य)

23 नवंबर देहरादून, शिलांग सेंग कुत्सनेम/ईगास-बग्वाल

27 नवंबर अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा/रहस पूर्णिमा

30 नवंबर बेंगलुरु कनकदास जयंती

# ईडी के लगाए पिंजरे को गच्चा दे गए केजरीवाल

परिवहन विशेष न्यूज

**परिवहन विशेष। एसडी सेठी।** इंफोरस्मेंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) ने कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुद्धवार 2 नवंबर को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया हुआ था। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर से लेकर राजघाट समेत कई जगहों पर आप कार्यकर्ताओ के संभावित धरना-प्रदर्शन को देखते हुए सडकों को बैरिकेट लगाकर छावनी में तब्दील कर दिया था। लेकिन अचानक से केजरीवाल का संदेश वायरल हो गया कि वह आज बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं होगें। सीएम केजरीवाल ने बाकायदा ईडी को पत्र लिखकर अपना जवाब भेज दिया।उन्होंने पत्र में चुनावी व्यस्तता,को बताया। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपने पत्र में भी आरोप लगाया कि जांच ऐजेंसी द्वारा भेजा गया नोटिस अवैध,राजनीति से प्रेरित और भाजपा की शह पर जारी किया गया है।उन्होने बताया कि उन्हें चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने जांच ऐजेंसी ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। वह इसे वापिस लेने की मांग करते हैं। बता दें कि ईडी के बुलावे पर यह आशंका व्यक्त की जार थी कि ईडी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले सकती है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में केजरीवाल के बाद कौन सीएम की कुर्सी को संभालेगा? इसके लिए बाकायदा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आतिषी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय,राघव चड्ढा तक के नाम संभावित मुख्यमंत्री बनने के नाम पर हवा में थे। वहीं

पूर्ण नियोजित भाजपा ने भी राजघाट पर पहले से ही कब्जा जमा लिया था। वहां कार्यकर्ताओ ने टेंट लगाकर सत्य ,और इमानदारी के भजन किए जा रहे थे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इस मामले में एक्सपर्ट का मानना है कि ईडी द्वारा दोबारा से पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस भेजा। जाएगा। ईडी के नोटिस पर नाफरमानी से ईडी को पहुंची ईगोइस्ट ठेस से जरूर एक्शन के मूड में होगी। बहरहाल ईडी की ईको क्या गुल खिलाएगी,ये तो वक्त ही बताएगा।गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के खास-खास वजीर अगवा नेता जिनमें मनीष सिसौदिया,संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जो पहले से ही ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है। इसके बाद राजा को भी घेरने की ईडी-सीबीआई की बिछाई बिसात को आज बुद्धवार को फिलहाल केजरीवाल ने मात दे दी है।

## बस मार्शल धरने पर अरविंदर सिंह लवली भी पहुंचे

**परिवहन विशेष। एस डी सेठी।** पिछले कई महीनों से डीटीसी बस मार्शलों का आंदोलन बकाया सैलरी और नौकरी पक्का करने को लेकर एलजी से लेकर सीएम सचिवालय, केजरीवाल आवास , परिवहन मंत्री, और डीटीसी हेडक्वार्टर तक पर जजबर्दस्त धरना-प्रदर्शन,चल रहा है।इस आंदोलन में महिला मार्शल समेत हजारों की संख्या में मार्शल मौजूद है। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पांच महीने का वेतन देना तो दूर उल्टे उनकी 1नवंबर से नौकरी तक को छीन लिया गया । इस बात से रात-दिन आंदोलित मार्शलों के बीच दिल्ली सचिवालय पर आमरण अनशन पर बैठे हजारों मारशलों के बीच कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपने पूरे दल बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मार्शलों के आंदोलन को अपना समर्थन देकर उनकी मांगों को सरकार से मनवाने की घोषणा तक कर डाली। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली धरने पर बैठे भूखंडो के बीच बैठे और उन्हें उनकी तमाम मांगों को मनवाने का आश्वासन दिया।उल्लेखनीय है कि आज बुधवार को महिला मार्शलों ने अपना करवा चौथ व्रत वहीं धरना स्थल पर किया। उनके साथ उनके बच्चे और सुहाग तक शामिल रहे।

## 'मिजोरम में आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है भाजपा', खरगे बोले- कांग्रेस प्रगति के लिए रहती है प्रतिबद्ध

**नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को भाजपा-आरएसएस पर मिजोरम में आदिवासियों की कीमती जमीन छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने दोस्तों की हित में ऐसा कर रही है। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) और जेडपीएम (जोराम पीपुल्स मूवमेंट) पर भी भाजपा के अनौपचारिक एजेंट होने का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की।

**'प्रगति के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही कांग्रेस'**

40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए सात नवंबर को होने वाले मतदान से पहले एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि मिजोरम के लोग शांति और प्रगति चाहते हैं और इसके हकदार भी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 में शांति समझौते के माध्यम से मिजोरम में शांति लाए और 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रही है।

**मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कुछ कहा?**

खरगे ने कहा कि भाजपा और आरएसएस विविधता और परिवर्तन के खिलाफ हैं और वे अपने मित्रों के कल्याण के लिए आदिवासियों की संपत्ति, कीमती जमीन और जंगल छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एमएनएफ और जेडपीएम भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

## सफाई और डीबीसी के कच्चे कर्मियों की बल्ले बल्ले

**परिवहन विशेष।एसडी सेठी।** दिल्ली नगर निगम में कच्चे के बतौर सालों से सफाई और डीबीसी कर्मचारियों पर केजरीवाल की नजरें इनायत हो गई हैं। एमसीडी के सदन की बैठक में मंगलवार को 58 में 54 प्रस्ताव पास किए गए हैं। मेयर शैली ऑबेरॉय और दिल्ली सीएम ने 5000 सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और डीबीसी कर्मियो को एमटीएस बनाने के अलावा निगम स्कूलों में पढने वाले गरीब बच्चों को यूनिफार्म के लिए 1100 रूपये प्रति छात्रगट भी दिए जाने की घोषणा कर दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों बतौर कच्चे के काम करने वालों की लम्बी लडाई के बाद नगर निगम ने उन्हें दिवाली का बडा तोहफा दे दिया है। इनमें 3100 डीबीसी कर्मचारी भी शामिल है। डीबीएस कर्मचारी जो सालों से अपने हक की लडाई लड रहे थे,उन्हें एटीएस बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि निगम के कच्चे सफाई कर्मचारियों व डीबीएस कर्मचारियों को पिछले कई सालों से पक्का करने का लॉली पॉप दिया जा रहा था। इस दरमियान निगम चुनाव भी हो गए। निगम की सत्ता पर आम आदमी। पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन केजरीवाल ने सुध नही ली। हारकर तमाम निगम के कच्चे कर्मचारी लाम बंद हो गए। मंगलवार को केजरीवाल ने 5000 निगम के कच्चे सफाई कर्मीयों को पक्का करने का ऐलान कर दिया।

## भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनिस के समर्थन में विजय संकल्प रैली 4 को

**बुरहानपुर।** भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) के समर्थन में विजय संकल्प रैली का आयोजन 4 नवंबर 2023 शनिवार को प्रातः 10 बजे से गणपति नाका से निकलेंगी तथा गांधी चौक में आमसभा होगी। विशाल आमसभा को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तथा भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) संबोधित करेंगे। भाजपा विजय संकल्प रैली गणपति नाका से आलमगंज, सिंधीपुरा गेट, बुधवारा, दाउदपुरा, ढोलीवाड़ा, अनाज मंडी, इकबाल चौक, सुभाष चौक होते हुए गांधी चौक पहुंचकर विशाल आमसभा में परिवर्तित होगी।

**अर्चना दीदी के स्वागत में उमड़ रहा जनसैलाब**

भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनिस ने ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जसौंदी, तारापाटी एवं चिल्लारा, पातोंडा, चिंचाला तथा शहरी क्षेत्र के प्रतापपुरा, सिलमपुरा एवं शिकारपुरा में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन मांगा। पुष्प वर्षा एवं आरती उतारकर महिला मतदाताओं ने श्रीमती चिटनिस का स्वागत किया।

**3 नवंबर का जनसंपर्क कार्यक्रम**

भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चिटनिस 3 नवंबर शुक्रवार को प्रातः8 बजे जामठी में जनसंपर्क करेंगी तो वहीं दोपहर 3.30 बजे गारबर्डी, 4 बजे ठाठर, 5 बजे बलड़ी, 6 बजे साग्यामाल, 6.30 बजे खामला, 7 बजे पांच पुल, 7.45 बजे मगरूल एवं 8.30 बजे मचलपुरा में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं से भाजपा को विजयी बनाने हेतु अपील करेंगी।

## भारतीय तेज गेंदबाजों के आगे श्रीलंकाई शेर हुए ढेर; ऐतिहासिक जीत दर्जकर शान से सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया टीम

भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच खेला गया। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शमी की घातक गेंदबाजी के चलते पूरी श्रीलंका टीम 19 .4 ओवर में 55 रन बनाकर सिमट गई। भारत की यह वनडे और वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत है।

**नई दिल्ली।** वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला। शमी-बुमराह और सिराज की धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने श्रीलंका को 302 रन से करारी शिकस्त दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी श्रीलंका टीम 19.4 ओवर में 55 रन बनाकर सिमट गई। अभी तक भारत ने अपने सभी सातों मैच जीते हैं और वह प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। भारत के लिए यह ऐतिहासिक जीत रही। भारत की वनडे और वर्ल्ड कप में यह सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा को 4 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद गिल और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला। शुभमन गिल अपना पहला वर्ल्ड कप शतक बनाने से चूक गए। गिल 92 रन के स्कोर पर आउट हुए। आउट होने से पहले विराट के साथ 189 रन की साझेदारी की।

**शतक से चूके तीन भारतीय बल्लेबाज**

वहीं, दर्शकों को विराट कोहली के 49वें शतक का इंतजार था, लेकिन वह भी अधूरा रह गया। विराट 88 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने तेज बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की खबर ली। श्रेयस ने 82 रन की पारी खेली। भारत ने 8 विकेट खोकर 357 रन बनाए। गेंदबाजी में श्रीलंका की ओर से दिलशान मधुशंका ने पांच विकेट झटके।

## डीडीए धमाका: 11 लाख में देगा दिवाली से पूर्व घर

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पहले आओ-पहले पाओ की शर्त पर हाउसिंग स्कीम - 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। डीडीए दिवाली से पहले 32500 फ्लैट्स के लिए आवेदन शुरू करने जा रहा है। इस बार डीडीए के 2बीएचके, 3 बीएचके और 4बीएचके) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

डीडीए के मुताबिक 24000 फ्लैट्स बनकर तैयार है। जबकि 8500 फ्लैट्स का निर्माण कार्य चल रहा है।जो कि 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस स्कीम के तहत - ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी,एचआईजी,, और सुपर एचआईजी के फ्लैट्स के साथ -साथ पेंट हाऊस भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स नरेला, द्वारका, सेक्टर 19बी, और सेक्टर-14 और लोकनायक पुरम में बताए गए है। इन फ्लैट्स की कीमतों पर गौर करें तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स-11 से 14 लाख, लाख रूपये में मिलेगे। वहीं एलआईजी-14- से 30 लाख में,एमआईजी-1 करोड से शुरू, एचआईजी-2.50 करोड रूपये से शुरू होगें। सुप्रीम एचआईजी-3 करोड रूपये की कीमत

रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5000 से ज्यादा फ्लैट्स होंगे। एमआईजी- में 1900 +, एचआईजी के 1600+ फ्लैट्स हैं। लोकनायक पुरम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 200+,एमआईजी कैटेगरी में 600+, हैं। इसी तरह द्वारका सेक्टर - 14 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1000 + एल आईजी कैटेगरी में 300 +,एमआईजी में भी 300+ फ्लैट्स हैं। कुल मिलाकर 32,500 फ्लैट्स है। इस बावत अधिक जानकारी के लिए डीडीए कॉल सेंटर के नंबर-1800-110-332 पर पूछताछ कर सकते हैं। बुकिंग ऑनलाईन होगी। डीडीए की वैबसाइट https://dda.govt.in पर भी अपडेट ले सकते हैं।

# कपिल मिश्रा ने कहा- आज केजरीवाल कह रहे ई.डी. नोटिस वापस ले, फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस ले

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ की रिश्वत ली गई है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में गुरुवार को ईडी के नोटिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, वो अपना नोटिस वापस ले ले. उनके इस बयान पर दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल कह रहे कि ई डी नोटिस वापस ले ले, कल कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले. सच यह है कि दिल्ली के सीएम ईडी के सवालों का सामना करने से बच रहे हैं. कपिल मिश्रा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ की रिश्वत ली गई है. उन्हें ईडी (ED) के सामने पेश होकर इसका जवाब देना होगा.

दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 338 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई है. उन्हें ईडी के सामने पेश होकर इसका जवाब देना होगा.कपिल मिश्रा ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जांच से भाग रहे हैं. अगर केजरीवाल ईमानदार होते तो ईडी के एक-एक सवाल का जवाब देते. दिल्ली सीएम का ईडी की जांच से भागना उनके अपराध का प्रतीक है.

कपिल मिश्रा आगे बोलते है सीएम अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और जरा सा भी उनमें सच बचा है तो वो जांच का सामना करें, लेकिन वो जांच से भाग रहे हैं. क्योंकि उन्हें पता है घोटाला हुआ है. दुर्योधन के सारे भाई जेल जा चुके हैं. दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने पाप किया है, उसकी सजा मिलेगी. आतिशी, मनीष सिसोदिया व अन्य नेताओं को जो झूठ बोला है उसका खुलासा करें. उनमें जरा सी भी सच्चाई बची है तो वो जांच का सामना करें.

## 18 साल होने से पहले ही चुनाव आयोग स्कूली बच्चों में रोपेगा लोकतंत्र के बीज, शिक्षा मंत्रालय से किया समझौता

चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटे चुनाव आयोग ने अब इस दिशा में एक और बड़ी पहल की है। इसके तहत अब वह भविष्य के ऐसे मतदाताओं को गढ़ेगा जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस दौरान इन सभी के बीच मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा जो स्कूलों में 6-12 कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा।

**नई दिल्ली।** चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटे चुनाव आयोग ने अब इस दिशा में एक और बड़ी पहल की है। इसके तहत अब वह भविष्य के ऐसे मतदाताओं को गढ़ेगा, जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस दौरान इन सभी के बीच मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह पहल मुख्य रूप से स्कूलों में छह से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों के बीच चलाई जाएगी।

चुनाव आयोग ने गुरुवार (2 नवंबर) को इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, इस पहल में 18 साल की उम्र पूरी से पहले ही बच्चों को लोकतंत्र के लिए मतदान क्यों जरूरी है, इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही मतदाता बनने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होंगे आदि की भी जानकारियां दी जाएगी।

**डेमोक्रेसी रूम बनाने का प्रस्ताव**

इसके तहत चुनाव आयोग ने सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के बीच वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक डेमोक्रेसी रूम भी बनाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, एनसीईआरटी के छह से लेकर बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भी वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इससे जुड़ी सामग्री भी शामिल की जाएगी।

**एनसीईआरटी सभी राज्यों को भी प्रस्ताव देगा**

इस दौरान एनसीईआरटी सभी राज्यों को भी अपने पाठ्यक्रम में इससे जुड़ी सामग्री शामिल करने के लिए प्रस्ताव देगा। चुनाव आयोग ने यह पहल ऐसे समय में की है, जब 18 साल की उम्र पूरी करने वाले मतदाता अब साल में चार बार अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पहले वह सिर्फ एक बार ही यानी एक जनवरी को 18 साल पूरे होने पर ही इसे जुड़वा सकते थे। इसके साथ ही आयोग ने वेटिंग मतदाताओं की भी सूची तैयार करने की पहल शुरु की है, जिसमें ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाता है, जिनकी उम्र अगले कुछ महीनों में ही 18 साल पूरी होने वाली है।

# पांडियन का इस्तीफा बीजे-बीजेपी की साजिश: क्योंझर कांग्रेस

मनोरंजन सासमल , ओडिशा

**भुबनेस्वर :** क्योंझर जिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम ओडिशा नवीन ओडिशा के अध्याख्य भि के पांडियन के इस्तीफे के नाटक के पीछे बीजे और बीजेपी दोनों हैं।

कांग्रेस नेता संगीता सिंह ने आज क्योंझर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन 5 सचिवों भि के पांडियन के स्वैच्छिक इस्तीफे को नाटक बताया है.कांग्रेस नेता संगीता ने शिकायत की, "20 अक्टूबर को वीके पांडियन ने अपने काम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया था। राज्य सरकार ने उसी दिन आवेदन केंद्रीय कर्मिक मंत्रालय को भेज दिया. 23 अक्टूबर को यानी 3 दिन के अंदर ही पांडियन का भिआरएस आवेदन केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया. इन तीन दिनों में से दो दिन केंद्र सरकार की छुट्टियां थीं. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वीके पांडियन के आवेदन को 48 घंटे में क्यों दी मंजूरी? क्या इससे पहले किसी आईएएस अधिकारी के मामले में केंद्र सरकार द्वारा इतनी तत्परता दिखाने की कोई मिसाल है? बल्कि जिन लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उन्हें वर्तमान केंद्र सरकार ने वापस कर दिया है.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि वीके पांडियन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बिजेडी-भाजपा सरकार की साजिश है। जिसका जवाब आने वाले 2024 के चुनाव में ओडिशा की जनता देगी. इसके साथ ही जिला कांग्रेस ने कहा है कि जिले में दिनोंदिन बढ़ रहे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न आदि के खिलाफ आंदोलन चलाया जायेगा. प्रेस वार्ता में अन्य लोगों के अलावा जिला अध्यक्ष मोहन परिदा, पीसीसी संपादक संग्राम

दास, कांग्रेस युवा अध्यक्ष सुनेस धीर, छात्र अध्यक्ष सुभम राज, सदर ब्लॉक अध्यक्ष उत्तम कुमार साहू प्रमुख रूप से उपस्थित थे.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023